● वर्ष-3
● अंक-190
रायपुर, रविवार
17 मार्च 2024
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.
samacharpacheesa@gmail.com

।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-6›› तृप्ति डिमरी के सितारे बुलंदी पर...

लोकसभा चुनाव की घोषणा

सात चरणों में मतदान, 4 जून को नतीजें

नई दिल्ली। आगामी लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम और चरणों की घोषणा के लिए चुनाव आयोग की तरफ से ब्रीफिंग की गई। चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान करते हुए बताया कि इस बार के चुनाव सात चरण में होंगे। 4 जून को पूरे देश में वोटों की गिनती होगी।

किस चरण में कितने सीटों पर वोटिंग

- **पहला चरण**- 20 मार्च को नोटिफिकेशन
  19 अप्रैल को वोटिंग- 102 सीट
- **दूसरा चरण**- 28 मार्च को नोटिफिकेशन
  26 अप्रैल को वोटिंग- 89 सीट
- **तीसरा चरण**- 12 अप्रैल को नोटिफिकेशन
  7 मई को वोटिंग- 94 सीट
- चौथा चरण- 18 अप्रैल को नोटिफिकेशन
  13 मई को वोटिंग- 96 सीट
- **पांच चरण**- 26 अप्रैल को नोटिफिकेशन
  20 मई को वोटिंग- 49 सीट
- **छठा चरण**- 29 अप्रैल को नोटिफिकेशन
  25 मई को वोटिंग- 57 सीट
- **सातवां चरण**- 7 मई को नोटिफिकेशन
  1 जून को वोटिंग- 57 सीट

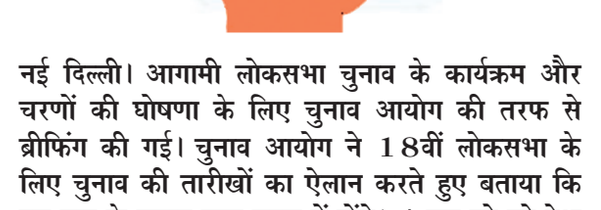

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हम तीन चरणों में कार्यक्रम की घोषणा करेंगे। सबसे पहले उपचुनाव के लिए। 26 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां उपचुनाव होने हैं। बिहार, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तमिलनाडु है।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि विभिन्न संचार माध्ययम से जुड़े मतादाओं का स्वागत है। सभी तीन साथ हैं और देश का गर्व। हम एक यादगार और निष्पक्ष चुनाव एक पर्व की तरह सब की भागीदारी के माध्यम से सुनिश्चित कराएंगे। राजीव कुमार ने कहा कि भौगोलिक, सांस्कृत रूप से इतने विविध देश में चुनाव कराने के लिए हमने आपको पिछले दो सालों में तैयार किया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस देश में कुल मतदाता 96.8 करोड़ हैं। जिनमें से 49.7 करोड़ पुरुष और 47 करोड़ महिलाएं है। 1.82 करोड़ पहली बार मतदाता इन चुनावों में हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारे पास कुल 96.8 करोड़ मतदाता हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारे पास 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता, 10.5 लाख मतदान केंद्र, 1.5 करोड़ मतदान अधिकारी और सुरक्षा कर्मचारी, 55 लाख ईवीएम, 4 लाख वाहन हैं।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना चुनौतियाँ

सीईसी ने चार सुश्री के माध्यम से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने में चुनौतियों पर प्रकाश डालाः बाहुबल, पैसा, गलत सूचना और एमसीसी उल्लंघन। उन्होंने आज के डिजिटल युग में गलत सूचना से निपटना जटिल है। हमने यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ उपाय किए हैं कि गलत सूचना को शुरू में ही खत्म कर दिया जाए। हम फर्जी खबरों को खारिज करने में सक्रिय हैं। फर्जी खबरों के प्रवर्तकों से मौजूदा कानूनों के अनुसार गंभीरता से निपटा जाना चाहिए।

चुनाव आयोग ने सुरक्षित मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कई प्रमुख बिंदुओं को प्राथमिकता दी है। इनमें निष्पक्षता के लिए अधिकारियों का स्थानांतरण, मतदान कर्मचारियों का यादृच्छिकीकरण और प्रत्येक बूथ पर मतदान एजेंटों की भागीदारी शामिल है। इन निर्देशों का उद्देश्य पारदर्शिता सुनिश्चित करना और पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई को रोकना है। इसके अतिरिक्त, संवेदनशील मतदान केंद्रों पर 24×7 एकीकृत नियंत्रण कक्ष और वेबकास्टिंग स्थापित की गई है। हिस्ट्रीशीटरों पर पूरी निगरानी के साथ ही सीमाओं पर ड्रोन आधारित चेकिंग होगी। सीईसी कुमार ने राजनीतिक दलों से व्यक्तिगत हमलों और अभद्र भाषा से परहेज करने का भी आग्रह किया। चुनाव आयुक्त ने कहा कि आगामी चुनावों के लिए 2,100 से अधिक सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों को तैनात किया जा रहा है, जो बल की तैनाती और कर्मियों और मशीनों के यादृच्छिकीकरण की निगरानी करेंगे और भय-मुक्त चुनाव कराएंगे। आयोग ने प्रवर्तन एजेंसियों को अवैध धन, शराब, ड्रग्स और मुफ्त वस्तुओं पर नकेल कसने का भी निर्देश दिया, जिससे 2022-23 के चुनाव चक्र में 11 राज्यों में 800% से 3,400 करोड़ रुपये की वृद्धि दर्ज की गई।

मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि चुनाव में खून-खराबे और हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने कहा, हमें जहां से भी हिंसा की सूचना मिलेगी, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।

कुमार ने कहा, चुनावों का लक्ष्य प्रमुख परिणाम हैं- नागरिक भागीदारी में वृद्धि और शून्य हिंसा। आयोग कम पुनर्मतदान, कोई प्रलोभन नहीं, स्पष्ट अभियान और फर्जी कथाओं पर अंकुश लगाने का प्रयास करता है। एक सफल चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। ईसीआई ने सभी हितधारकों के लिए 27 ऐप और पोर्टल की भी पेशकश की है, जिसमें सीविजिल भी शामिल है जो नागरिकों को एमसीसी उल्लंघनों की रिपोर्ट करने और 100 मिनट के भीतर कार्रवाई का आश्वासन देने का अधिकार देता है।

मतदान के दौरान कैसी होगी सुरक्षा व्यवस्था?

चुनावी प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए देश भर में लगभग 1.5 करोड़ मतदान अधिकारियों को तैनात किया गया है।

बहुप्रतीक्षित सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीईसी कुमार ने कहा कि सभी पक्षों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा सीएपीएफ को पर्याप्त रूप से तैनात किया जाना है और प्रत्येक जिले में एकीकृत नियंत्रण कक्षों द्वारा सहायता प्रदान की जानी है। निगरानी सुनिश्चित करने के लिए चेक पोस्ट और ड्रोन। मतदाताओं का विश्वास सुनिश्चित करना सर्वोपरि है। चुनावों में हिंसा अस्वीकार्य है। नकल करने वालों को तेजी से दंडित किया जाना चाहिए।

अंक क्या कहते हैं?

चुनाव आयोग के मुताबिक, पूरे भारत में 97 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं जो आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान करेंगे। इनमें 49.70 करोड़ पुरुष मतदाता और 47.10 करोड़ महिला मतदाता हैं. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, हमारे पास 1.8 करोड़ पहली बार मतदाता हैं और 20-29 वर्ष की आयु के बीच 19.47 करोड़ मतदाता हैं।

ईसीआई ने आगे कहा कि 82 लाख दिव्यांगजन, 2.2 लाख 100+ और 48,000 तीसरे लिंग के मतदाता चुनाव में भाग लेंगे। 85 लाख से अधिक पहली बार महिला मतदाता चुनाव में भाग लेंगी और 12 राज्यों में मतदाता लिंग अनुपात लगभग 1,000 है

लोकसभा चुनाव के लिये तैयार, लोकतंत्र के भविष्य का होगा फैसलाः कांग्रेस

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के बाद शनिवार को कहा कि वह इस चुनावी मुकाबले के लिए तैयार है तथा यह चुनाव आम नहीं, बल्कि खास है क्योंकि इसमें देश के लोकतंत्र के भविष्य का फैसला होगा। पार्टी के मीडिया विभाग के प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा, ''चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है। यह चुनाव आम नहीं है। यह चुनाव फैसला करेगा कि यह देश और लोकतंत्र मजदूर किसान के कंधों पर चलेगा या कुछ उद्योगपतियों के कंधों पर चलेगा।'' उन्होंने कहा, ''इस चुनाव से तय होगा कि देश बाबासाहेब के संविधान पर चलेगा या एक तानाशाह के गुणगान पर चलेगा। इसलिए यह एक आम चुनाव नहीं, खास चुनाव है।'' खेड़ा ने कहा, ''हम तैयार हैं।'' उन्होंने कांग्रेस की पांच 'न्याय गारंटी' का उल्लेख करते हुए कहा कि देश के युवाओं, किसानों और अन्य वर्गों को विश्वास है कि कांग्रेस ने जो वादा किया है उन्हें वह पूरा करेगी।

छत्तीसगढ़ में 11 सीटों पर तीन चरणों में होंगे मतदान

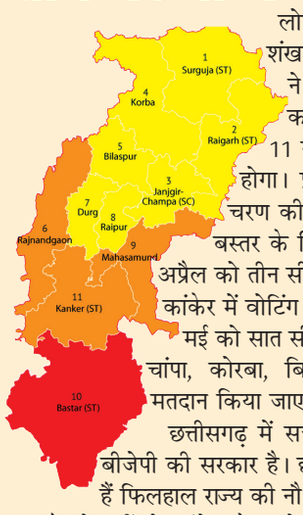

लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शंखनाद हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का एलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर तीन चरणों में मतदान होगा। प्रदेश में 19 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी जिसमें एक सीट बस्तर के लिए मतदान किया जाएगा। 26 अप्रैल को तीन सीटों राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर में वोटिंग होगी। वहीं तीसरे चरण में सात मई को सात सीटों सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर में मतदान किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद अब यहां बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं फिलहाल राज्य की नौ लोकसभा सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, तो वहीं दो कांग्रेस के खाते में हैं।

भाजपा ने सभी 11 सीटों पर उम्मीदवारों का एलान कर दिया जबकि कांग्रेस ने अभी तक छह प्रत्याशियों का ही एलान किया है। पांच सीटों पर घोषणा बाकी है। भाजपा ने रायपुर लोकसभा सीट से बृजमोहन अग्रवाल, दुर्ग से सीट से विजय बघेल, राजनांदगांव सीट से संतोष पांडेय, सरगुजा सीट से चिंतामणि महाराज, बिलासपुर सीट से तोखन साहू, कोरबा सीट से सरोज पांडेय, महासमुंद सीट से रूप कुमारी, रायगढ़ सीट से राधेश्याम राठिया, बस्तर सीट से महेश कश्यप, कांकेर सीट से भोजराज नाग और जांजगीर से कमलेश जांगड़े को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस ने राजनांदगांव से पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कोरबा से ज्योत्सना महंत, रायपुर से विकास उपाध्याय, जांजगीर चांपा से शिवकुमार डहरिया, महासमुंद से ताम्रध्वज साहू, राजेन्द्र साहू को कांग्रेस ने दुर्ग से प्रत्याशी घोषित किया है जबकि पांच सीटों पर अभी उम्मीदवार उतारना बाकी है।

2019 में कब हुआ था चुनाव

2019 के लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल से लेकर 19 मई के बीच सात चरणों में हुए थे। छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में मतदान हुए थे।चुनाव आयोग ने राज्य में 11 अप्रैल 2019, 18 अप्रैल 2019 और 23 अप्रैल 2019 को तीन चरणों में मतदान की घोषणा की थी। 2019 में 11 अप्रैल को बस्तर, 18 अप्रैल को राजनांदगांव, महासमुंद, कांकेर और 23 अप्रैल को सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर-चंपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर में वोटिंग हुई थी। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नौ और कांग्रेस ने दो सीटों पर जीत हासिल की थी। वहीं, 2014 के चुनाव में बीजेपी ने 10 और कांग्रेस ने एक सीट जीती थी। इसके अलावा 2009 में बनी यूपीए सरकार के दौरान बीजेपी ने 10 और कांग्रेस को सिर्फ एक सीट ही मिली थी।

प्रमुख समाचार

राहुल मुंबई में रविवार को पदयात्रा निकालेंगे

मुंबई। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी मुंबई में रविवार को मणि भवन से अगस्त क्रांति मैदान तक 'न्याय संकल्प पदयात्रा' निकालेंगे। पार्टी के एक नेता ने यह जानकारी दी। गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' का समापन शनिवार शाम को यहां डॉ. बी आर आंबेडकर के स्मारक चैत्य भूमि पर होगा। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार के कार्यालय ने कहा कि सांस्कृतिक और सामाजिक क्षेत्रों की प्रतिष्ठित हस्तियां गांधी के साथ पदयात्रा में शामिल होंगी। इसके बाद गांधी अगस्त क्रांति मैदान के पास तेजपाल हॉल में प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। महात्मा गांधी जब भी मुंबई में होते थे, तो मणि भवन उनका निवास स्थान होता था, जबकि कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर, 1885 को तेजपाल हॉल में हुई थी। राहुल गांधी की यात्रा से जुड़ी समापन रैली मुंबई के शिवाजी पार्क में रविवार को आयोजित होगी, जिसमें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव समेत विपक्षी गठबंधन 'इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस' (इंडिया) के विभिन्न दलों के नेता शामिल होंगे।

देश की सारी हकीकत बताने के लिए यात्रा-प्रियंका

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुईं, जो मुंबई के धारावी तक पहुंची। यात्रा बाद में शाम को दादर की चैत्यभूमि पर समाप्त हो गई, जो प्रसिद्ध सामाजिक प्रतीक बाबासाहेब अम्बेडकर का स्मारक है। 14 जनवरी को संघर्षग्रस्त मणिपुर से शुरू हुई यात्रा शनिवार को 63वें दिन पड़ोसी ठाणे से मुंबई में प्रवेश कर गई। एआईसीसी महासचिव (संगठन) केसी वेणुगोपाल और राज्य के एआईसीसी प्रभारी रमेश चेन्नितला एक खुली जीप में गांधी भाई-बहन के साथ थे। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा आज राहुल गांधी की 6,700 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा समाप्त हो जाएगी। यह यात्रा उन्होंने आपको इस देश की सारी हकीकत बताने के लिए आयोजित की थी। आज, इस देश की वास्तविकता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जनजागरण पर तीखा हमला हो रहा है और आप सभी को इससे अवगत कराने के लिए उन्होंने (राहुल गांधी) भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू की है।

घर तोड़े जाने के मामले में आजम दोषी करार दिये गये

रामपुर। रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने डूंगरपुर में जबरन घर तोड़े जाने के मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री आजम खान समेत चार आरोपियों को दोषी करार दिया जबकि तीन अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। अदालतसोमवार, 18 मार्च को इस मामले में सजा सुनाएगी। संयुक्त निदेशक (अभियोजन) रोहताश कुमार पांडेय ने बताया कि रामपुर की सांसद-विधायक अदालत (एमपी-एमएलए कोर्ट) के सत्र न्यायाधीश विजय कुमार नेजिले के गंज थाने में दर्ज एक मामले में शनिवार को पूर्व मंत्री मोहम्मद आजम खान, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और पूर्व पुलिस क्षेत्राधिकारी (सीओ) आले हसन तथा बरकत अली को दोषी करार दिया जबकि अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया। उन्होंने बताया कि इस मामले में सजा के लिए 18 मार्च की तारीख मुकर्रर की गयी है। उन्होंने बताया कि रामपुर के चर्चित डूंगरपुर मामले में समाजवादी सरकार के समय जबरन घर तोड़े जाने की घटना को लेकर तत्कालीन नगर विकास मंत्री आजम खान, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान और तत्कालीन सीओ (शहर) आले हसन खान सहित कुल सात आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धाराओं 447, 427, 504, 506, 395 और 412 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

दिल्ली शराब घोटाला, कविता को 7 दिन की ईडी रिमांड

नई दिल्ली। भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता को दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तारी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने शनिवार को दिल्ली की एक अदालत में पेश किया। अदालत ने कविता को 23 मार्च तक पूछताछ के लिए हिरासत में रखने का जांच एजेंसी का अनुरोध स्वीकार कर लिया। कोर्ट में के कविता ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध% बताया। दिल्ली के राउज़ एवेन्यू कोर्ट में पेश किए जाने पर उसने कहा कि यह एक अवैध गिरफ्तारी है, इसके खिलाफ लड़ूंगी। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) प्रमुख और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी, 46 वर्षीय एमएलसी को शुक्रवार को हैदराबाद में गिरफ्तार किया गया और कल देर रात दिल्ली लाया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने अदालत से उसकी 10 दिन की हिरासत की मांग की, जबकि उसके बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया, क्योंकि उन्होंने जांच एजेंसी की कार्रवाई को अवैध कहा था, क्योंकि इस मामले में कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने की उसकी याचिका सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है और सूचीबद्ध है।

अमेरिका को कनाडा के साथ जोड़ना गलत-एस जयशंकर

नई दिल्ली। केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को खालिस्तानी मुद्दे पर उत्तरी अमेरिकी देशों के साथ भारत के संबंधों पर टिप्पणी की और कहा कि अमेरिका को कनाडा के साथ जोड़ना अनुचित होगा। उन्होंने इंडिया खालिस्तानी मुद्दे पर भारत की चिंताओं और अमेरिका और कनाडा द्वारा नई दिल्ली के खिलाफ लगाए गए आरोपों के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। जयशंकर ने जवाब दिया कि आप अमेरिका और कनाडा का निर्बाध रूप से उपयोग करते रहें। मैं कई कारणों से वहां एक रेखा खींचूंगा। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि सभी ने कहा और किया है, अमेरिकी राजनीति ने हिंसक, चरमपंथी विचारों और गतिविधियों को उस तरह की जगह नहीं दी है। कनाडा ने ऐसा किया है। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए उन्हें एक साथ रखना उचित है। मैं दोनों के बीच अंतर करूंगा।

अमित शाह का एएनआई के साथ साक्षात्कार

सीएए भाजपा के लिए संवेदना का मुद्दा है

मोदी सरकार सभी पात्र शरणार्थियों को नागरिकता देगी: अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को समाचार एजेंसी एएनआई पॉडकास्ट को दिए गए इंटरव्यू में भारत सरकार द्वारा हाल ही लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में विपक्षी दलों द्वारा फैलाए जा रहे झूठ के तथ्यों को सामने रखा और इस अधिनियम के असली उद्देश्य को देश की जनता के साथ साझा किया। साथ ही उन्होंने कई विषयों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। **(भाग-1)**

श्री शाह ने सिर्फ मुसलमानों को इस अधिनियम के तहत नागरिकता नहीं दिए जाने के प्रश्न पर कहा कि पाकिस्तान पूरी तरह से मुसलमानों के लिए दिया गया था। देश का बंटवारा हुआ और मुस्लिम आबादी लिए अखंड भारत का एक हिस्सा दिया गया जो पाकिस्तान है। अगर मुसलमानों को भी नागरिकता दी जाए तो फिर तो किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति आकर नागरिकता मांग सकता है। अखंड भारत के जिन लोगों के साथ धार्मिक प्रताड़ना हुई है, उनको शरण देना हमारी नैतिक और संवैधानिक जिम्मेदारी है। आंकड़े देखने पर पता चलता है कि विभाजन के समय पाकिस्तान में 23 प्रतिशत हिंदू और सिख तो जो आज महज 3 प्रतिशत बचे हैं, 1951 में पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) में हिंदू आबादी 22 प्रतिशत थी और 2011 में मात्र 10 प्रतिशत रह गए, अफगानिस्तान में 1992 में लगभग 2 लाख हिंदू और सिख थे लेकिन आज मात्र 500 बचे हैं। आंकड़ों में ये बदलाव साफ दिखाता है कि उन लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ और इन्हें दोयम दर्जे के नागरिक की तरह रखा गया। जब भारत एक था तब वो हमारे ही भाई - बहन थे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने अहमदिया और बलोच प्रताड़ना पर कहा कि पाकिस्तान में शिया, अहमदिया और बलोच के साथ होने वाली प्रताड़ना आंकड़ों से सिद्ध नहीं होती है और पूरे विश्व में सभी प्रकार के मुस्लिमों को एक मुस्लिम माना जाता है। ध्यान देने लायक बात ये है कि किसी भी मुस्लिम के लिए भारत की नागरिकता लेने का रास्ता बंद नहीं किया गया है। कोई भी मुस्लिम नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है और जो संवैधानिक नियम और पात्रता है उनके पूरे होने पर उसे नागरिकता मिल जाएगी। सीएए केवल एक विशेष नियम है जिसके तहत आवेदन करने के लिए एक पोर्टल बनाया गया है और जिन शरणार्थियों के पास दस्तावेज नहीं है उनके लिए रास्ता ढूंढा जाएगा। लेकिन लगभग 85 प्रतिशत से अधिक शरणार्थियों के पास

दस्तावेज हैं जिनके आधार पर वे आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की कोई समय सीमा नहीं रखी गई है। देश की सभी भाषाओं में ये आवेदन किया जा सकता है।

श्री शाह ने दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा जताई गई अपराध बढ़ने आशंका पर कहा कि अरविंद केजरीवाल अपने भ्रष्टाचार के उजागर होने से अपना आपा खो बैठे हैं। वो शायद भूल गए हैं ये सभी लोग भारत में ही रहे हैं और इस नियम से सिर्फ अधिकार और औपचारिक नागरिकता दी जा रही है। 2014 तक जो लोग आ गए सिर्फ उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अगर उन्हें देश की इतनी चिंता है तो वो क्यों बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात नहीं करते और क्यों रोहिंग्या घुसपैठियों का विरोध नहीं करते। अरविंद केजरीवाल वोटबैंक की राजनीति करते हैं। दिल्ली का चुनाव उनके लिए लोहे के चने चबाने जैसा हो गया है। नौकरी का हक तो बंगाल में आए रोहिंग्या घुसपैठिए मारते हैं लेकिन उनका केजरीवाल ने कभी विरोध नहीं किया। अपने वोटबैंक और तुष्टिकरण की ओछी राजनीति के कारण ये सिर्फ हिंदू, बौद्ध और सिख शरणार्थियों का विरोध करते हैं। अरविंद केजरीवाल विभाजन की पृष्ठभूमि को भूल चुके हैं। श्री शाह ने केजरीवाल को सलाह दी कि उन्हें उन निराश्रित शरणार्थियों के साथ कुछ समय गुजारना चाहिए जो अरबों की संपत्ति छोड़कर भारत में आए थे और यहां दिल्ली में सब्जी की दुकान लगाने लगे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका दिवस मनाकर एक ऐतिहासिक काम किया है। केजरीवाल को समझ नहीं आता कि जब धर्म के आधार पर अलग कर महिलाओं की इज्जत लूटी जाती है तो वे किस वेदना से गुजरते हैं। इन लोगों की क्या गलती है कि इन लोगों के बच्चों को अस्पताल में एडमिट नहीं किया जाता है, अच्छी नौकरी नहीं मिलती है, अपने नाम से संपत्ति नहीं खरीद सकते, मतदान नहीं कर सकते। विभाजन का फैसला इन शरणार्थियों ने नहीं कांग्रेस ने लिया था। **(क्रमश)...**

रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र के 47 कार्यों हेतु 15 करोड़ से अधिक राशि स्वीकृत

■ बीटी व सीसी रोड, 20 लाख लीटर के ओव्हर हेड टेंक व विभिन्न स्थानों पर मुक्तिधाम के निर्माण कार्य स्वीकृत

रायगढ़। राज्य शासन ने नगर निगम रायगढ़ अंतर्गत विभिन्न 47 निर्माण तथा विकास कार्यों के लिए 15 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की है। प्रदेश के वित्त मंत्री व रायगढ़ विधायक श्री ओ.पी.चौधरी की पहल से निर्माण कार्यों के प्रस्ताव को उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरूण साव स्वीकृति प्रदान की है। इन निर्माण कार्यों में शहर के भीतर डामरीकृत सड़कों व सीसी रोड निर्माण को प्राथमिकता से शामिल किया गया है। इसके साथ ही 20 लाख लीटर के ओव्हर हेड टेंक का निर्माण भी शामिल है जिससे शहर के भीतर जल आपूर्ति में सुविधा होगी। शहर में विभिन्न स्थानों पर मुक्तिधाम के निर्माण भी स्वीकृत किए गए है। स्वीकृत कार्यों में अधोसंरचना मद अंतर्गत 25 कार्यों के लिए 7 करोड़ 99 लाख 22 हजार रूपये स्वीकृत किए गए है। वहीं 15 वे वित्त आयोग के अनटाईड ग्रांड अंतर्गत 20 कार्यों के लिए 4 करोड़ 69 लाख 80 हजार व टाईड ग्रांड जल प्रबंधन हेतु 2 कार्यों के लिए 2 करोड़ 41 लाख 95 हजार सहित कुल 15 करोड़ 10 लाख 97 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी स्वीकृति आदेश के अनुसार रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत अधोसंरचना मद अंतर्गत स्वीकृत 25 कार्यों में 48 लाख 50 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 48 बोईरदादर चौक से शालिनी स्कूल तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 34 लाख 97 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 18/19 तुलसी होटल से गांधी प्रतिमा एवं मालधक्का रोड तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 48 लाख 58 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 21 बेलादुला स्कूल से पीपल पेड़ तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 49 लाख 33 हजार रुपये की लागत से उर्दना में मेन रोड से 6 वीं बटालियन ऑफिस तक बीटी सड़क निर्माण कार्य, 50 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 42 अमलीभौना प्राथमिक शाला से बाबाधाम मुख्य मार्ग से बस्ती तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 15 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक मेन रोड से सहदेवपाली बस्ती तक सीसी रोड निर्माण कार्य, 35 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 08/09 रियापारा चौक से संबरी स्प्रे पेंटिंग शॉप चांदमारी (रामपुर मेन रोड)तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 35 लाख 15 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 41 छातामुड़ा मेन गेट से बस्ती तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 01 करोड़ 21 लाख 73 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 37 शंकर टिम्बर (पुलिया)से बेनीकुंज तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 17 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 33 गांधी नगर से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से मेन रोड तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 03 लाख 50 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 22 उदासी घर से माखीजा घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य, 12 लाख 50 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 45 भगवानपुर शिव मंदिर से स्कूल तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 30 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 27 गुरू द्रोण स्कूल से शिशुपाल घर तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 23 लाख 80 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 23 चक्रधरनगर चौक से गांगुली घर कसेर पारा तक सीसी सड़क निर्माण कार्य, 05 लाख 39 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 9 लता सदन से पप्पू किराना तक सीसी रोड निर्माण कार्य, 09 लाख 96

हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 38 रेखा ब्यूटी पार्लर से सोनकर घर एवं जायसवाल घर से महंत घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य, 04 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 32 पंडा घर से पप्पू घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य, 20 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 2 में बुजबधान तालाब के पास नाला निर्माण कार्य, 42 लाख 98 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 10 मधुवन मस्जिद से बाबा सिंह घर तक सीसी रोड निर्माण कार्य, 36 लाख 83 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 10 एस.एल.आर.एम.सेंटर के बगल में मुक्तिधाम निर्माण कार्य, 20 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 28 में पंजरी प्लांट के पास मुक्तिधाम निर्माण कार्य, 40 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 10 सीएमएचओ तिराहा भगवानपुर मुक्तिधाम में बाउण्ड्रीवाल, दरवाजे एवं पाथवे निर्माण कार्य, 30 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 29 में कयाघाट मुक्तिधाम में पाथवे, शेड एवं अन्य निर्माण कार्य, 30 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 47 मरघट्टी पारा विजयपुर में पाथवे, शेड एवं अन्य निर्माण कार्य व 35 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 4 जगतपुर मुक्तिधाम निर्माण कार्य के काम शामिल है।

इसी प्रकार 15 वे वित्त आयोग अनटाईड ग्रांड अंतर्गत स्वीकृत कार्यों में 12 लाख 55 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 2 में लक्ष्मण घर से शीतला मंदिर तथा शीतला मंदिर से गोविन्द भवन तक सीसी सड़क निर्माण कार्य, 6 लाख 80 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 3 में फिरत ओंगरे घर से रेमिश बैंक घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य, 7 लाख 9 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 4 जगतपुर में मुख्य मार्ग (जीएसटी कार्यालय) के पास से पिन्टु शर्मा घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य, 10 लाख 8 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 5 बापू नगर में केजीएन होटल से शौकी सिंह घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य, 15 लाख 32 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 18 पोस्ट ऑफिस के पीछे ओम मोबाईल से सांसद निवास तक बीटी सड़क निर्माण कार्य, 15 लाख 35 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 19 सुभाष चौक श्याम मंदिर के पास आरसीसी नाली निर्माण कार्य, 22 लाख 05 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 20 शहीद चौक से शनि मंदिर तक बीटी सड़क निर्माण कार्य, 5 लाख 44 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 21 शशि घर से गुप्ता घर तक आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य, 29 लाख 83 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 22 सुरभि डेयरी से सुमित घर की ओर मुख्य मार्ग के पास तक बीटी रोड निर्माण कार्य, 14 लाख 80 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 24 मोदी नगर में पौनी पसारी के पास नाला निर्माण कार्य, 88 लाख 76 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 26/27 जियो मार्ट के सामने से हाऊसिंग बोर्ड बिल्डिंग तक अतरमुड़ा रोड बीटी सड़क निर्माण कार्य, 15 लाख 77 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 27 में शुभ ब्यूटी पार्लर से जगन्नाथ पुरम कालोनी तक बीटी सड़क निर्माण कार्य, 40 लाख 53 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 28/29 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से मिनी माता चौक तक बीटी सड़क निर्माण कार्य, 4 लाख 13 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 29 जेल काम्पलेक्स से शनि मंदिर पुलिया तक आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य, 32 लाख 70 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 29/30 पंडित दीनदयाल गार्डन से कयाघाट चौक तक बीटी सड़क निर्माण कार्य, 05 लाख 07 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 37 प्रायमरी हेल्थ सेंटर मेन रोड से नामदेव महिलाने घर तक सीसी सड़क निर्माण कार्य, 05 लाख रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 39 दीपमाला घर से रेलवे बंगलापारा स्कूल जयहिंद गली तक सीसी रोड एवं बाक्स कल्वर्ट निर्माण कार्य, 09 लाख 84 हजार रूपये की लागत से वार्ड क्रमांक 45 टाटा शोरूम से हनुमान नाला तक आर.सी.सी.नाली निर्माण कार्य, 80 लाख 20 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 47 क्रेजी फास्ट फूड सेंटर से विजयपुर चौक से इंदिरा विहार चौक तक बीटी सड़क निर्माण कार्य, 48 लाख 49 हजार रुपये की लागत से मुख्य मार्ग के दोनों ओर फुटपाथ निर्माण कार्य शामिल है। साथ ही 15 वे वित्त आयोग अंतर्गत टाईड ग्रांड जल प्रबंधन के तहत 72 लाख 39 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 19 टाऊन हाल निगम कार्यालय फिडर लाईन एवं डिस्ट्रीब्यूशन बिछाने का कार्य तथा 01 करोड़ 94 लाख 18 हजार रुपये की लागत से वार्ड क्रमांक 19 टाऊन हाल परिसर में 20 लाख लीटर क्षमता का ओव्हर हेड टेंक का निर्माण कार्य शामिल है।

धान खरीदी में 73 लाख का घोटाला करने वाले आरोपी को कारावास

सक्ती। सक्ती जिले में धान खरीदी में 73 लाख का घोटाला मामले में कोर्ट ने कडारी केंद्र प्रभारी को तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। सक्ती न्यायालय की मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट गंगा पटेल ने सजा सुनाई है। बता दें कि 10 साल बाद कोर्ट का यह फैसला आया है, जिसमे कोर्ट ने तत्कालीन खरीदी केंद्र प्रभारी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई है।

सहायक जिला अभियोजन अधिकारी अरविन्द कुमार जायसवाल ने बताया कि वर्ष 2013-14 में कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा के आदेश पर पी.के पाण्डेय, खाद्य अधिकारी, के.के शर्मा नायब तहसीलदार चांपा, जी.आर भतरा सहकारिता अधिकारी, एस.पी.सोनी संग्रहण केन्द्र प्रभारी एवं गिरधारी लाल राठौर को मिलाकर संयुक्त जांच दल का गठन कर विभिन्न धान खरीदी केन्द्र का निरीक्षण किया गया था। इसी क्रम में 18 फरवरी 2014 को सेवा सहकारी समिति कडारी के अधीनस्थ धान उपार्जन केन्द्र का निरीक्षण कर जांच किया गया। जिसमें तत्कालीन प्रभारी समिति अशोक सिंह ठाकुर के द्वारा धान खरीदी से संबंधित दस्तावेज को जांच दल के सामने पेश किया गया। जिसमें भौतिक सत्यापन करने पर लगभग 4495.78 क्विंटल धान, अनुमानित कीमत 73 लाख रुपए का धान कम होना पाया गया।

जिसके बाद जांच दल ने एसडीएम चांपा के माध्यम से कलेक्टर जिला जांजगीर चांपा को रिपोर्ट प्रेषित किया और मामले की शिकायत बाराद्वार थाना बाराद्वार में की। जिस पर थाना बाराद्वार के द्वारा धारा 409, 34 भा.द.वि. के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना किया गया था। मामले में विवेचना दौरान नारायण गबेल और किशोर सिंह की संलिप्तता पाए जाने पर थाना बाराद्वार द्वारा दोनों को भी आरोपी बनाया गया था। प्रकरण में विवेचना उपरांत आरोपी अशोक सिंह, नारायण गबेल और किशोर सिंह के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया था। मामले की सुनवाई गंगा पटेल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय सक्ती के समक्ष हुई थी। जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी अशोक सिंह को दोष सिद्ध पाते हुए 3 साल की सजा और 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। जबकि अन्य 2 अभियुक्त को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त कर दिया गया है।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका भर्ती मामले में मंत्री ने लिया संज्ञान

मुंगेली। एक तरफ जहां मुंगेली जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में धांधली का मामला लगातार सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने संज्ञान में लेकर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में गड़बड़ियों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं।

बता दें कि महिला एवं बाल विकास विभाग के मुंगेली ब्लॉक परियोजना कार्यालय में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती में गड़बड़ियों की ढेरों शिकायत है। विभाग में उच्च अधिकारी और कलेक्टर के समक्ष गड़बड़ी से जुड़े कई मामले पहुंच चुके हैं। जिसकी जांच तो चल रही है, लेकिन जांच की आंच किसी तक नहीं पहुंच सकी है। जिसका फायदा भर्ती कर रहे विभाग के अफसर मनमानी रवैय्ये पर उतर आए हैं। यहां के कारनामे आए दिन मीडिया में सुर्खियां बटोरती रहते हैं। यही वजह है कि अब मंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। दरअसल जिले के प्रभारी मंत्री लखनलाल देवांगन ने अधिकारियों की बैठक लेकर विभागवार केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का समीक्षा किया और अफसरों कोआवश्यक

निर्देश भी दिए हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग मंत्रालय ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के लिए जारी गाइडलाइन को दरकिनार कर मुंगेली जिले के जिला मुख्यालय स्थित एकीकृत बाल विकास परियोजना कार्यालय मुंगेली-1 पदस्थ अधिकारी प्रमिला पांडेय के द्वारा खुद से मनमाफिक नियम बनाकर चहेते अभ्यर्थी को लाभ दिलाने अलग-अलग भर्ती नियम बनाकर भर्तियां की जा रही है। यह बात हम नहीं, बल्कि हाल में कांग्रेसियों के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को दिए गए लिखित शिकायत में उल्लेखित है। शिकायत में यह भी कहा गया है पैसे का लेनदेन कर परियोजना कार्यालय के अधिकारियों द्वारा गड़बड़ियों को अंजाम दिया जा रहा है।

भिलाई में प्रवीण तोगड़िया, कहा-

देशभर के हिंदुओं की रक्षा के लिए हर हफ्ते होगा हनुमान चालीसा

भिलाई। अंतरराष्ट्रीय विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के दौरे पर है। भिलाई में कैंप 2 में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। बता दें बजरंग दल ने देशभर में हर सप्ताह हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करने का अभियान शुरू किया है। जिसमे शामिल होने तोगड़िया भिलाई पहुंचे।

बजरंग दल की तरफ से हर गली मोहल्ले में हनुमान चालीसा का पाठ शुरु किया जा रहा है। बंजरग दल के कार्यकर्ताओं का दावा है कि हिन्दू राष्ट्र निर्माण के साथ साथ हिन्दुओं की रक्षा का भी दायित्व वह संभालेंगे। इसी के आयोजन में तोगड़िया भिलाई पहुंचे।

राष्ट्रीय बंजरग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि हिंदुओं के शौर्य से अयोध्या में राम मंदिर बन गया है। सुरक्षित हिंदू, समृद्ध हिंदू, सम्मान युक्त हिंदू इसलिए भारत में एक लाख जगह पर हर सप्ताह हनुमान चालीसा करने का अभियान शुरू किया है।

प्रवीण तोगड़िया ने कहा हनुमान चालीसा कर बजरंग दल के सदस्य हिंदू परिवार की सुरक्षा समृद्धि और सम्मान का काम करेंगे।

सीएए की तारीफ करते हुए तोगड़िया ने कहा कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के हिंदुओं को भारत की नागरिकता मिल रही है। इस कानून का फायदा हिंदुओं को भी होगा। देश मे हो रहे सीएए के विरोध को लेकर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र है विरोध चलता रहता है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

कांकेर के सरकारी अस्पताल में मोबाइल की रोशनी में इलाज

कांकेर। भानुप्रतापपुर में एक युवती ट्रेन से गिरकर घायल हो गई। उसे इलाज के लिए सरकारी अस्पताल लाया गया। जिस समय घायल लड़की अस्पताल पहुंची उस समय बिजली गुल थी। जिससे युवती का इलाज डॉक्टरों को मोबाइल की रोशनी में करना पड़ा। मामले ने तूल पकड़ा तो सीएमएचओ अविनाश खरे सामने आए। उन्होंने कहा कि सोलर पैनल में खराबी के कारण अस्पताल में बिजली चली गई थी। इस वजह से उस समय युवती का इलाज मोबाइल की रोशनी में करना पड़ा। सोलर पैनल ठीक कर लिया गया है। अब अस्पताल में बिजली की पूरी व्यवस्था है। अस्पताल में इस तरह से इलाज करने पर स्टाफ को फटकार भी लगाई गई हैं । सीएमएचओ अविनाश खरे ने कहा युवती जब अस्पताल में इलाज के लिए पहुंची तो तब लाइट गोल थी। उस दौरान जनरेटर स्टार्ट करने का समय नहीं मिला। युवती को मामूली खरोच थी। इस वजह से मोबाइल की रोशनी में मरहम पट्टी की गई। इस मामले की जांच की जा रही है। जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

नौ निरीक्षक और दो सहायक उप निरीक्षकों का तबादला

जगदलपुर। बस्तर पुलिस अधीक्षक ने आचार संहिता से पहले जिले में सर्जरी करते हुए नौ निरीक्षक और दो सहायक उप निरीक्षक को तबादला कर दिया है। जिसमे लंबे समय से सायबर सेल का प्रभार संभाल रहे सुरेश जांगड़े को कोतवाली का प्रभार दिया है, वहीं कोतवाली थाना प्रभारी लीलाधर को बोधघाट थाना भेजा गया है। बता दें कि बस्तर पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा के द्वारा बस्तर जिले के अलग- अलग थानों में पदस्थ आलाधिकारियों को इधर से उधर किया है, जिसमें सुरेश जांगड़े को सायबर सेल से कोतवाली थाना प्रभारी, लीलाधर राठौर को कोतवाली से बोधघाट, दिलबाग सिंह को रक्षित केंद्र से परपा थाना, दिनेश यादव को बकावंड से भानपुरी थाना, टामेश्वर चौहान को लोहंडीगुड़ा से नगरनार थाना, गणेश राम को परपा से लोहंडीगुड़ा, क्षत्रपाल कंवर रक्षित केंद्र से बकावंड, शिवानंद सिंह को नगरनार से प्रभारी सायबर सैल, कविता धुर्वे को बोधघाट से रक्षित केंद्र जगदलपुर, भवानी राम कश्यप को परपा से लोहंडीगुड़ा, सहायक उप निरीक्षक प्रमोद सिन्हा को कोड़ेनार से चित्रकोट भेजा गया है।

सरगुजा में हवाई सेवा के लिये मिला एरोड्रम लाइसेंस

सरगुजा। अंबिकापुर के मां महामाया एयरपोर्ट को घरेलु उड़ान के लिए डीजीसीए से एरोड्रम लाइसेंस मिल गया है। बीसीएएस ने गुरुवार को आखिरी बार निरीक्षण के बाद आचार संहिता लागू होने के पहले एयरपोर्ट से नियमित रूप से हवाई सेवा के संचालन की अनुमति दे दी है। लाइसेंस जारी होने के बाद अब जल्द ही एयरलाइंस कंपनी दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा का संचालन शुरू करेगी। अंबिकापुर से जल्द शुरू होगी घरेलु उड़ानः मां महामाया एयरपोर्ट से घरेलु उड़ान सेवा शुरू करने को लेकर सालों से कोशिश की जा रही थी। साल 2017 में इसे उड़ान योजना के तहत शामिल कर राशि की स्वीकृति दी गई। उसके बाद एयरपोर्ट में टर्मिनल भवन, रनवे, एटीसी टावर सहित दूसरे निर्माण कार्य, 20 सीटर विमान के हिसाब से कराए गए। लेकिन बाद में दोबारा भारत सरकार द्वारा इस एयरपोर्ट से 72 सीटर विमानों के उड़ान की योजना बनाई गई। 47 करोड़ रुपए की राशि से रनवे की लम्बाई बढ़ाने करने के साथ ही इसकी क्षमता में विस्तार किया गया।

दिनदहाड़े महिला शिक्षक के घर बोला धावा

कोरबा। कोरबा में चोरों की सक्रियता कितनी बढ़ गई है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब पॉश कॉलोनियों के मकान भी सुरक्षित नहीं हैं। दर्री थानांतर्गत एनटीपीसी के यमुना विहार स्थित एक शिक्षिका के घर को निशाना बनाते हुए अज्ञात चोरों ने 1 लाख 70 हजार रुपयों की चोरी कर ली। दोपहर के वक्त हुई चोरी की जानकार देर शाम सामने आई। बताया जा रहा है कि शिक्षिक अपनी ड्युटी पर चली गई थी, जबकि पुत्र भी काम पर चला गया था। घटना शुक्रवार दोपहर करीब एक बजे की घटना है जब चोरी की जानकारी मिली तब पुलिस को सूचित किया गया। मकान मालकिन रागनी चौहान ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल यमुना विहार में वह शिक्षिका के पद पर पदस्थ हैं। वह सुबह करीब नौ बजे स्कूल चली गई और उसका बेटा भी कम पर निकल गया। पति और बेटी बिलासपुर किसी काम से चले गए थे। घर पर केवल बहू ही थी, जो ऊपर बालकनी वाली क्वाटर में थी। सुबह नौकरानी काम करने के बाद नीचे ताला लगाकर बहू को चाबी देकर चली गई।

मां मनका दाई मंदिर में चोरी, लाखों रुपये पार

जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा जिले के ग्राम खोखरा में प्रसिद्ध मां मनका दाई मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। मंदिर से पांच नग दान पेटी, चांदी का लोटा, एक नथनी और देवी मां के पहने हुए करधन की चोरी हुई है। चोरों ने अपने चेहरे को कपड़ों से ढका हुआ है। वहीं चोरी करते सीसीटीवी कैमरे में तीन चोर कैद हुए हैं, दानपेटी के बगल में चौकीदार सोया हुआ है, जिसे चोरी का पता नहीं चल पाया। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार, प्रसिद्ध मंदिर मां मंदिर दाई में शुक्रवार की बीती रात अज्ञात चोरों ने मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर में अब तक 5वीं बार चोरी हुई है, आज शनिवार की सुबह जब पुजारी मंदिर में पूजा करने पहुंचा तो देखा कि मंदिर में रखे सामान बिखरे हुए थे, वहीं पांच नग दान पेटी नहीं थे। वहीं मंदिर के अंदर देवी मां के पहने हुए एक नथनी, करधान भी नहीं था। मंदिर में चोरी की घटना की जानकारी मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों और पुलिस को घटना की जानकारी दी गई। मौके पर पुलिस टीम पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की।

पहली ड्रोन दीदी के रूप में चित्ररेखा साहू का चयन

■ सीएम साय ने सौंपी चाबी, महिलाओं को दी जाएगी ट्रेनिंग

बालोद। देश में महिलाओं को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोदी सरकार ने %नमो ड्रोन दीदी% योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत, महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव से संबंधित ट्रेनिंग दी जाएगी। बालोद जिले से पहली ड्रोन दीदी के रूप में चित्ररेखा साहू का चयन हुआ है वो इस अभियान से जुड़कर काफी खुश हैं और उन्होंने बताया कि लगातार यहां ड्रोन को लेकर ऑर्डर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चित्ररेखा साहू को नमो ड्रोन की चाबी भी सौंप दी।

आज कल कृषि में लागत काफी बढ़ गया है ऐसे में मजदूर मिलना भी काफी मुश्किल रहता है। ऐसे में ड्रोन की सहायता

से दवा का छिड़काव करना एक बेहतर विकल्प हो सकता है। ऐसे में यहां पर चित्ररेखा साहू को लगातार बालोद जिले में काम मिलने लगा है औसतन दवा छिड़काव के लिए तीन लोगों को जरूरत होती है पर ड्रोन की सहायता से केवल एक व्यक्ति ड्रोन संचालित कर सकता है।

नमो ड्रोन स्कीम से क्या होगा फायदा?

ड्रोन दीदी स्कीम के कई फायदे होंगे। इसके जरिये महिलाओं को सशक्त बनाना पहली प्राथमिकता है। यह स्कीम उन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और दक्षता में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। यह स्कीम कृषि में लगने वाली लागत में कमी ला सकती है। इससे रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। नमो ड्रोन दीदी योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल है।

10 लीटर की क्षमता

ड्रोन दीदी ने बताया कि इस ड्रोन में दवा छिड़काव के लिए 10 लीटर की क्षमता है और 10 लीटर का दवा एक एकड़ खेत के लिए पर्याप्त होता है इससे कृषि कार्यों में काफी तेजी देखने को मिलेगी, साथ ही महिलाओं को इस क्षेत्र में अग्रसर होकर काम करना चाहिए अभी तो सरकार चाहती है कि और भी ढूंढ दे दिया ब्लॉक से लेकर जिला और जिले से लेकर पूरे प्रदेश में काम करें महिलाओं की भागीदारी क्षेत्र में सुनिश्चित हो यही सरकार का प्रयास है मैं इस योजना से जुड़ी हूं मुझे काम मिलने लगा है और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।

काम सीखने हुई दिक्कत

चित्ररेखा साहू ने बताया कि ड्रोनेस सीखने के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि जो कक्षाएं लगती थी ग्वालियर में मुझे प्रशिक्षण दिया गया परंतु वहां अंग्रेजी कक्षा के चलते मुझे काफी दिक्कतें होती थी और सब पढ़े-लिखे लोग थे और मैं एक कम पढ़ी-लिखी सामान्य परिवार की महिला थी परंतु मैंने हिम्मत नहीं हारी और धीरे-धीरे इसे सीखने की कोशिश करती रही और अब मैं पूरी तरह पारंगत हो चुकी हूं।

कोयलीबेड़ा में मुठभेड़, एक नक्सली ढेर

कांकेर। बस्तर में लाल आतंक को एक बार फिर जवानों के सामने घुटने टेकने पड़े हैं। कोयलीबेड़ा में एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों की टीम जब कोयलीबेड़ा पहुंची तो नक्सलियों ने गोलीबारी शुरु कर दी। माओवादियों की ओर से की गई गोलीबारी के बाद जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया। घात लगाकर किए गये हमले का मुंहतोड़ जवाब जवानों ने दिया। जवानों को भारी पड़ता देख मौके से नक्सली भाग खड़े हुए। मुठभेड़ वाली जगह से एक नक्सली की डेड बॉडी बरामद हुई है। मारे गए नक्सली की अभी पहचान नहीं हो पाई है।

मुठभेड़ वाली जगह से जब नक्सली भाग निकले तब जवानों ने इलाके में सघन सर्चिंग अभियान चलाया। सर्च ऑपरेशन के दौरान घटनास्थल से एक वर्दीधारी नक्सली का शव बरामद हुआ है। नक्सली के शव के पास से एक स्टेनगन और बम में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान भी बरामद हुआ हैं। नक्सलियों ने जवानों की टीम पर हमला उस वक्त किया जब जवान सर्चिंग अभियान से वापस कैंप की

ओर लौट रहे थे। कोयलीबेड़ा के चिलपरस जंगलों में बीते दिनों भी नक्सलियों के साथ जवानों की मुठभेड़ हुई थी। मुठभेड़ के दौरान जवानों के जवाबी हमले से घबराकर नक्सली भाग गए थे। पूरे बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता मिल रही है। सरकार की कोशिश है कि विकास की रफ्तार बस्तर के जंगलों में रहने वाले लोगों को तक पहुंचे। जवानों के नए कैंप भी बस्तर में बनाए जा रहे हैं। कैंप बनाए जाने के बाद से नक्सली बौखलाहट में हैं।

संक्षिप्त समाचार

आचार संहिता लगने से ठीक पहले तीन आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर

रायपुर। लोकसभा चुनाव के लिए देशभर में आज शनिवार को आचार संहिता लग गई है। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार अधिकारियों का तबातोड़ फेरबदल किया है। कई अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपे तो कई का प्रमोशन भी हुआ। इसी क्रम में आज आचार संहिता लगने से ठीक पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के तीन अधिकारियों का ट्रांसफर किया है। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, कबीरधाम अपर कलेक्टर अविनाश भोई का जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी कोंडागांव में ट्रांसफर किया गया है। वहीं महासमुंद के अपर कलेक्टर निर्भय कुमार साहू को अब कबीरधाम जिला अपर कलेक्टर का पद सौंपा गया है। इसके साथ ही कोंडागांव के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नीलम टोप्पो को ट्रांसफर मंत्रालय नवा रायपुर में हुआ है।

पूर्णेन्दु सक्सेना बने मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संघ चालक; पहली बार छत्तीसगढ़ से चुने गए

रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रांत संघ चालक डॉ. पूर्णेन्दु सक्सेना को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मध्य क्षेत्र के क्षेत्र संघ चालक चुना गया है। ऐसा पहली बार हुआ कि छत्तीसगढ़ प्रांत से क्षेत्र संघ चालक चुना गया है। नागपुर में संघ की आयोजित अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में उनका निर्वाचन हुआ। उनका क्षेत्र संघ चालक चुने जाने पर छत्तीसगढ़ आरआरएस इकाई में हर्ष का माहौल है।

आरपीएफ़ में सब इंस्पेक्टर एवं कांस्टेबल के 4660 रिक्त पदों पर निकाली भर्तियाँ

बिलासपुर। रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ़) में सब इंस्पेक्टर के 452 एवं कांस्टेबल के 4202 कुल 4660 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है । इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 अप्रैल से शुरू होकर 14 मई 2024 तक पूर्ण की जाएगी। उपरोक्त भर्ती के लिए सब इंस्पेक्टर के पद पर निर्धारित योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक एवं आयु सीमा 20 से 28 वर्ष तथा कांस्टेबल के पद पर निर्धारित योग्यता भारत सरकार से मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10 उतीर्ण या समकक्ष एवं आयु सीमा 28 से 28 वर्ष रखा गया है रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ़) द्वारा जारी गई इन रिक्तियों पर भर्ती हेतु योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल होने के लिए निर्धारित तिथियों में ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म भर सकेंगे । इस संबंध में और अधिक जानकारी 2 से 08 मार्च के रोजगार समाचार में एवं रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट पर प्राप्त की जा सकती है ।

सड़क चौड़ीकरण एवं दो विकास कार्यों के लिए प्रशासकीय स्वीकृति मिली

महासमुंद। महासमुंद जिले में पुल पुलिया निर्माण एवं सड़क चौड़ीकरण के दो विकास कार्यों के लिए राज्य शासन के लोक निर्माण विभाग द्वारा कुल 35 करोड़ 51 लाख 7 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। जारी प्रशासकीय स्वीकृति आदेश के तहत राज्य शासन द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में महासमुंद जिला अंतर्गत महासमुंद, तुमगांव, अछोला मार्ग लंबाई 9.65 किलोमीटर के सड़क चौड़ीकरण निर्माण की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 27 करोड़ 18 लाख 30 हजार रुपए स्वीकृत किया गया है। इसी तरह भगत सरायपाली से रायगढ़ सीमा मार्ग तक कुल 5.50 किलोमीटर पुल पुलिया निर्माण सहित निर्माण के लिए 8 करोड़ 32 लाख 77 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है।

भूपेश सरकार में पास हुए विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। आचार संहिता लगने से पहले कांग्रेस अलग-अलग मुद्दों को लेकर भाजपा को घेरने में लगी हुई है। कांग्रेस के रायपुर लोकसभा से प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने शनिवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर डॉ। गौरव सिंह को विधायक सम्मान निधि में पैसों के आवंटन और भाजपा सरकार के बाद निधि के कार्यों में लगी रोक का ज्ञापन सौंपा है। विकास उपाध्याय के साथ पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा और पंकज शर्मा सहित सभापति प्रमोद दुबे और जिला अध्यक्ष गिरीश दुबे भी मौजूद रहे।

कार्टून युद्ध पर कांग्रेस के आरोप पर उप मुख्यमंत्री ने किया पलटवार

कहा- नैतिकता की बात कांग्रेस को शोभा नहीं देता

रायपुर। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा के बीच सोशल मीडिया में कार्टून युद्ध शुरू हो चुका है। इसके साथ ही कांग्रेस के भाजपा पर राजनीति के स्तर को नीचा गिराने से सवाल पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में किसने राजनीति का स्तर गिराया, प्रशासनिक स्तर को गिराया, यह जनता देख रही है। नैतिकता की बात करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि चिंतामणि महाराज एक बड़े वर्ग के सम्माननीय हैं। कांग्रेस में वे लंबे समय तक रहे, और भाजपा में अब उनके घर वापसी हुई है। समाज के बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, इसलिए उनके लिए इस तरह की बातें करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने चुनाव की तारीखों के एलान को लेकर कहा कि भाजपा पूरी तरह से मजबूती से चुनाव की मैदान में है। वहीं कांग्रेस के ऐसे हालात हैं कि प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे। कांग्रेस की टिकट पर कोई लड़ने को तैयार नहीं है।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने मीडिया से चर्चा में कहा कि भाजपा चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। विधानसभा के चुनाव समाप्त होते ही भाजपा लोकसभा की तैयारी में जुट गई थी। लगातार बैठक हो रही हैं। विधानसभा के सम्मेलन पार्टी ने शुरू कर

दिए हैं। प्रत्याशी भी घोषित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी ने आम जनता के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। इसलिए आम जनता ने तय किया है कि तीसरी बार देश की बागडोर प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे।

वहीं प्रशासनिक फेरबदल पर कांग्रेस के बयान पर अरुण साव ने कहा कि प्रशासनिक फेरबदल रूटिंग के प्रशासनिक काम है। कांग्रेस देश के विकास पर छत्तीसगढ़ के विकास पर बात करे। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। आम लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन आया है। इन मुद्दों पर कांग्रेस बात करे। कांग्रेस आज मुद्दाविहीन है, नेतृत्व विहीन है, और नियत विहीन है, इसलिए आज कोई कांग्रेस की टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा है।

भाजपा ने अबकी बार कार्टून के जरिए बैज पर साधा निशाना

भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कार्टूनों के जरिए कांग्रेस प्रत्याशियों पर हमला बोल रही है। ताजा कड़ी में बस्तर सांसद दीपक बैज को 'धर्मांतरण स्पेशलिस्ट' करार देते हुए कार्टून जारी किया है, जिसमें वे क्रास लिए हुए सोनिया गांधी से कह रहे हैं कि अगर उन्हें प्रत्याशी बनाया गया तो वे धर्मान्तरण के रिकार्ड तोड़ देंगे।

बता दें कि भाजपा ने छत्तीसगढ़ में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कार्टूनों का सहारा लिया है। इसकी शुरुआत राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से की थी, जिन्हें जिहादी गिरोह का अगुवा बताते हुए राजनांदगांव को जिहादगांव बनाने का आरोप लगाया था।

भाजपा ने केवल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर ही नहीं बल्कि कार्टूनों के जरिए जांजगीर-चांपा प्रत्याशी शिव डहरिया, कोरबा प्रत्याशी ज्योत्सना महंत, रायपुर प्रत्याशी विकास उपाध्याय और महासमुंद प्रत्याशी पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पर निशाना साधा था। ताजा कड़ी में बस्तर से सांसद और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष दीपक बैज पर निशाना साधा है।

भाजपा के जवाब में कांग्रेस ने भी जारी किया कार्टून

रायपुर। लोकसभा चुनाव के तारीख के एलान से पहले ही भाजपा की ओर से छेड़े गए कार्टून युद्ध का अब कांग्रेस ने भी जबाव देना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने रायपुर से भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल और सरगुजा से चिंतामणी महाराज से जुड़ा कार्टून जारी किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने इस कार्टून युद्ध के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए राजनीति के स्तर को गिराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस का मानना रहा है कि राजनीतिक मुद्दे होने चाहिए, जन सरोकार के मुद्दे होने चाहिए। भाजपा ने कांग्रेस प्रत्याशियों का पोस्टर जारी किया। संस्कृत श्लोक शठे शाठ्यम समाचरेत का पालन करते हुए कांग्रेस ने भी भाजपा के साथ वैसा ही किया है। शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस ने शुरू से प्रयास किया कि वर्तमान सरकार के 10 साल के काम और राज्य सरकार के तीन महीने के काम को लेकर जनता के बीच जाएंगे। किसानों, युवाओं और महिलाओं के लिए जो वादा किया है, उसे लेकर जनता के बीच जाएंगे। वहीं चिंतामणि महाराज के कार्टून में वाशिंग मशीन का उपयोग करने पर कहा कि वे जब कांग्रेस में थे, तब श्वष्ठ ने पत्र लिखकर एसीबी को कहा था कि कथित कोल घोटाले में 5 लाख रुपए लिया। जैसे ही भाजपा में शामिल हुए एसीबी ने एफआईआर दर्ज किया। श्वष्ठ के पत्र के आधार पर 7 लोगों के खिलाफ स्वष्ठक दर्ज किया, लेकिन चिंतामणि महाराज को बरी कर दिया। भाजपा ज्वाइन करते ही मोदी वाशिंग मशीन में धुलकर पाक साफ हो गए।

सुशील आनंद शुक्ला ने इसके साथ रायपुर और कांकेर के भाजपा प्रत्याशी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि रायपुर प्रत्याशी के समता कॉलोनी मामला किसी से छुपा नहीं है। वहीं कांकेर प्रत्याशी पर भी महिला के साथ दुर्व्यवहार के आरोप लगे हैं। भाजपा ने अनर्गल और मिथ्या आरोप के पोस्टर जारी किए थे। कांग्रेस ने प्रत्याशियों पर जो आरोप कभी ना कभी लगे हुए हैं, उसे सामने लाने का प्रयास किया है। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष ने लोकसभा चुनाव की तारीखों के एलान और प्रत्याशी सूची पर कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी पूरी है। बूथ लेवल के कार्यकर्ता पूरी तरह से अलर्ट है। चुनाव आयोग आज चुनाव की घोषणा करता है, तो पूरी तरह सजग है। कांग्रेस के 6 प्रत्याशियों की घोषणा हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। तमाम सीटों पर जल्द कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो जाएंगे। वहीं प्रदेश में हुए प्रशासनिक फेरबदल पर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि एक शेर है, उम्र भर गालिब मैं यही भूल करता रहा धूल चहरे पर थी, पर आईना साफ करता रहा।

भ्रष्टाचारी पर इतनी मेहरबानी क्यों ?

3 साल बीतने के बाद भी भ्रष्ट सरंपच पर नहीं चला हंटर

लोरमी। मुंगेली जिले के लोरमी जनपद अंतर्गत ग्राम पंचायत डिंडोल में सरपंच पर ग्रामीणों ने अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जहां ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत डिंडोल के सरपंच रामनिवास के खिलाफ धारा 40 के तहत कार्रवाई के आदेश के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे नाराज ग्रामीणों ने जल्द कार्रवाई की मांग को लेकर लोरमी एसडीएम को लिखित में ज्ञापन सौंपा है।

आरोप है कि वर्तमान सरपंच के द्वारा कई कार्यों में अनियमितता कर भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी शिकायत 3 साल पहले की गई थी। जिसकी जांच के बाद मुंगेली जिला पंचायत के द्वारा शिकायत को सही पाया गया। इसके साथ ही सरपंच के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए धारा 40 के तहत कार्रवाई करने आदेश भी जारी किया गया है।

इसके बावजूद आज तीन साल बीत जाने के बाद भी सरपंच को बर्खास्त करने की कार्रवाई नहीं की गई है और आज भी वह स्वतंत्र रूप से भ्रष्टाचार में लिप्त होकर कार्य कर रहा है। वहीं ग्रामीणों ने यह भी कहा कि बिना किसी राजनीतिक दबाव में आए सरपंच के खिलाफ पूर्व की लंबित धारा 40 के तहत तत्काल बर्खास्त करने की कार्रवाई सहित वर्तमान सरकार में जीरो टारलेन्स भ्रष्टाचार मुक्त सरकार और प्रशासन का एक मिसाल कायम हो सके। साथ ही एक संदेश उन लोगों को भी जाए जो पद में रहकर सेवा नहीं भ्रष्टाचार करते हैं। बहरहाल देखना होगा इस पूरे मामले में कब तक जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा कार्रवाई की जाती है।

प्रदेश की सभी 11 सीटें भाजपा जीतेगी : केदार कश्यप

वन मंत्री का कोरबा दौरा, पार्टी नेताओं के साथ की चर्चा

कोरबा। लोकसभा चुनाव के तहत कोरबा में बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरु हो गया है। इसी कड़ी में शनिवार को प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप कोरबा पहुंचे। कोरबा जैसे हाईप्रोफाइल सीट को जीतने के लिए भाजपा एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। मंत्री केदार कश्यप का हेलीकॉप्टर जैसे ही एसईसीएल के हेलीपैड पर उतरा वैसे ही भाजपाइयों में उत्साह का संचार हो गया।

इस मौके पर कोरबा संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय भी मौके पर मौजूद रही। मीडिया से चर्चा के दौरान मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि प्रदेश की सभी 11 सीटें भाजपा जीतेगी। केदार कश्यप ने यह भी बताया कि कोरबा और बस्तर से बीजेपी हारी थी इसे लेकर इस बार विशेष तैयारी की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर और उनकी योजनाओं को लेकर लोग इस बार भाजपा को वोट देकर जीत दिलवाएंगे।

केदार कश्यप ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़

में किंग कोबरा को लेकर एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है कोरबा में किंग कोबरा को लेकर एक टीम काम कर रही है आने वाले समय में कोरबा में किंग कोबरा की पर्याप्त मौजूदगी को देखते हुए वनमंत्री ने यहां स्नैक पार्क बनाने की घोषणा की है। स्नेक पार्क बनाने की तैयारी को लेकर काम शुरू कर दिया गया है सर्वे और इलाके किंग कोबरा को लेकर ग्रामीणों से भी पूछताछ की जा रही है।

सभी सीटें जीतेगी भाजपा- सरोज

कोरबा संसदीय सीट से भाजपा की प्रत्याशी सरोज पांडेय का मानना है कि अपने पांच वर्ष के कार्यकाल में वर्तमान सांसद ने कुछ नहीं किया है, यही वजह है कि इस बार जनता विकास के नाम पर भाजपा को मौका देगी। सरोज पांडेय ने एसईसीएल हेलीपेड पर मीडिया से चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे है। देश के विकास के लिए उन्होंने जो किया है वह किसी ने नहीं किया है।

भाजपा प्रत्याशी सरोज पाण्डेय ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे देश में माहौल है देश के प्रधानमंत्री का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना तय है कोरबा देश के विकास और मजबूती के लिए निश्चित ही लोग बीजेपी को वोट करेंगे।

इलेक्टोरल बॉन्ड पर कांग्रेस के आरोप पर सरोज पांडेय का पलटवार, कहा-

कोई घोटाला है तो प्रमाणित करके दिखाएं

गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही। कांग्रेस के इलेक्टोरल बॉन्ड पर उठाए गए सवाल पर कोरबा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडेय पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कोई नैतिक आधार नहीं है। जो खुद दलदल में डूबे हुए हैं, वह हम पर आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस के पास इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कोई सबूत है, और कोई घोटाला है, तो इसे प्रमाणित करके दिखाएं।

कोरबा लोकसभा से भाजपा की प्रत्याशी सरोज पांडे ने अपने लोकसभा क्षेत्र के मरवाही विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ आगामी चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक की। इस दौरान अपने कार्यकर्ताओं से मिलते हुए धनपुर के दुर्गा देवी मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए राज्य की खुशहाली की मांग की और अपनी और केंद्र सरकार की जीत की कामना की।

इस अवसर पर मीडिया से चर्चा में उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों के दौरान किसी भी आरोप में भाजपा की सरकार में किसी मंत्री ने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने राहुल गांधी को कोट करते हुए कहा कि उन्हें याद होगा कि 2014 के पहले उनकी सरकार के कितने मंत्रियों ने घोटालों के कारण इस्तीफे दिये थे। वहीं ष्ठ को लेकर कहा कि यह देश की जरूरत है। देश की अस्मिता और अखंडता की बात जहां आएगी, वहाँ हमारी सरकार इसे मजबूती से लागू करेगी, हम वोट की राजनीति नही करते है।

कोरबा लोकसभा को लेकर सरोज पांडेय ने कहा कि आगामी कोरबा लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस कही नहीं दिखाई देती है। वो मुकाबले में ही नहीं है। कांग्रेस के पास नेतृत्व नहीं है, मुद्दे ही नहीं है। वर्तमान कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत को निष्क्रिय बताते हुए कहा कि पिछले 5 साल वे यहां की सांसद हैं। इस क्षेत्र के लिए क्या किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जनता का विश्वास है, उन विश्वास पर जनता पर फिर से आशीर्वाद देगी।

केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 240 ई-बस की दी मंजूरी

छत्तीसगढ़ के कई शहरों में दौड़ेगी प्रधानमंत्री ई-बस

रायपुर। केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के संचालन के लिए छत्तीसगढ़ के चार शहरों को मंजूरी दी है। राजधानी रायपुर, कोरबा, भिलाई-दुर्ग और बिलासपुर को इस योजना का लाभ मिला है। प्रदेश को 240 ई-बसों की स्वीकृति मिली है। केन्द्र सरकार से रायपुर शहर को सार्वजनिक परिवहन के लिए 100 इलेक्ट्रॉनिक बसें मिलेंगी।

केन्द्र सरकार ने रायपुर के लिए 100, कोरबा के लिए 40, भिलाई-दुर्ग के लिए 50 और बिलासपुर के लिए 50 ई-बसों की स्वीकृति प्रदान की है। देश के 169 शहरों ने सार्वजनिक परिवहन की प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए अपना डीपीआर केन्द्र सरकार को प्रस्तुत किया था, जिसमें से राजधानी रायपुर सहित चयनित अन्य शहरों को इस सेवा का लाभ मिला है। अब इन शहरों को सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-बस सेवा की सुविधा मिलेगी।

रायपुर कलेक्टर डॉ. गौरव कुमार सिंह के मार्गदर्शन में नगर निगम रायपुर ने सार्वजनिक परिवहन के लिए ई-बस सेवा की सुविधा के लिए भारत सरकार के इस योजना में चयनित होने विस्तृत कार्य योजना प्रतिवेदन केन्द्र सरकार को प्रेषित किया था। नगर निगम आयुक्त अबिनाश मिश्रा ने बताया है कि सितंबर माह में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा के लिए 169 शहरों में से 100 शहरों ने चयन के लिए अपनी दावेदारी केन्द्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी। रायपुर सहित छत्तीसगढ़ के कोरबा, भिलाई-दुर्ग, बिलासपुर ने ई-बस सेवा योजना में चयन हेतु अपना विस्तृत कार्य योजना के साथ अपनी दावेदारी की थी।

नारी न्याय गारंटी और महतारी वंदन योजना पर महिलाओं ने दी प्रतिक्रिया

रायपुर। लोकसभा चुनाव से पहले महिलाओं को केंद्र में रखते हुए कांग्रेस ने नारी न्याय गारंटी योजना की घोषणा की है। इसके तहत महिलाओं को सालाना एक लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाएगी। वहीं दूसरी ओर भाजपा के महतारी वंदन योजना के तहत सालाना 12,000 रुपये यानी महीने के 1,000 रुपये महिलाओं को मिलना शुरू हो चुका। महिलाओं को अपने खेमे में करने के लिए अपनी गारंटियों के साथ दोनों ही पार्टियां भरपूर प्रयास में जुटी हुई है। इस पर मीडिया की टीम ने महिलाओं की राय जानने का प्रयास किया है।

रायपुर के पुरानी बस्ती निवासी सुषमा भारत का कहना है

कि महंगाई के इस दौर में आर्थिक सहायता मिलना हमारे लिए मदद करती है। बच्चों की पढ़ाई से लेकर घर की आवश्यकताओं में इन पैसों से मदद हो जाती है। वहीं पुरानी बस्ती की ही निवासी पारो बाई सपाहा का कहना है कि भाजपा की सरकार पहले ही महिलाओं को 1 हजार की राशि देकर मदद कर रही है। हमें इससे ज्यादा की आवश्यकता नहीं है। लालच करना और देना दोनों ही गलत है।

सब्जी का व्यापार करने वाली रूखमणी पटेल का कहना है कि हम मेहनत से काम कर खाने में सक्षम है, यदि सरकार कुछ देना चाहती है तो वे रोजगार दे। मेरी बेटी ने बहुत पढ़ाई की है, लेकिन वह एक निजी संस्थान में काम करने पर मजबूर है, क्योंकि सरकार नियुक्तियां नहीं कर रही है। वहीं फूलों का व्यापार करने वाली सुनीता भारत कहती है कि हम उसे ही चुनेंगे जो ज्यादा देगा और बेहतर योजना लाएगा। अब मोदी की गारंटी और कांग्रेस की नारी न्याय गारंटी किस प्रकार देश की आधी आबादी पर काम करेगा ये लोकसभा चुनाव के बाद ही स्पष्ट होगा।

घायल की मदद कर जान बचाने वाले 6 लोगों को एसएसपी ने किया सम्मानित

■ मरीन ड्राइव में ट्रैफिक बूथ का किया गया उद्घाटन

रायपुर। सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और घायलों को त्वरित उपचार के लिए उच्चतम न्यायालय ने सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित चिकित्सा उपलब्ध कराने वाले व्यक्तियों को गुड सेमेरिटंस अर्थात नेक व्यक्ति की संज्ञा देते हुए इन्हें प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने को निर्देशित किया गया है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर संतोष कुमार सिंह सड़क दुर्घटना में घायलों को त्वरित सहायता पहुंचाकर जान बचाने वाले 6 गुड सेमेरिटंस को कंट्रोल रूम में सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात-प्रोटोकाल अनुराग झा और उपपुलिस अधीक्षक यातायात रायपुर गुरजीत सिंह उपस्थित रहे।

बता दें कि भारत देश में प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में लगभग डेढ़ लाख लोगो की मृत्यु होती है, जिसका प्रमुख कारण घायलों को त्वरित चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध नहीं होने के कारण होता है। सड़क दुर्घटना के दौरान 30 मिनट का समय गोल्डन आवर कहलाता है। इस दौरान यदि घायल व्यक्ति को किसी भी प्रकार से हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया जाता है या फिर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करा दिया जाता है तो घायल की जान बचाई जा सकती है। लेकिन अधिकांश सड़क दुर्घटनों में लोगों को बार-बार

पेशी जाना पड़ेगा और पुलिस द्वारा बार-बार पूछताछ के लिए आना पड़ेगा। परेशानी होगी सोचकर मोबाइल फोन से वीडियो फोटो बना लिया जाता है, लेकिन घायल की जान बचाने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, जिससे घायल व्यक्ति त्वरित उपचार के अभाव में तड़प-तड़प कर दम तोड़ देता है। जिसे ध्यान रखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर संतोष कुमार सिंह द्वारा सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि थाना क्षेत्र में घटित सड़क दुर्घटना में घायल को त्वरित सहायता पहुंचाने के लिए गुड सेमेरिटंस का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने और घायल को त्वरित सहायता पहुंचाकर जान बचाने वाले गुड सेमेरिटंस को प्रोत्साहित और पुरस्कृत करने के लिए उपस्थित कराने निर्देशित किया गया है।

इसी क्रम में रायपुर जिले में घटित विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटंस को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जिला रायपुर संतोष कुमार सिंह द्वारा मोंमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। साथ ही इनका फोटो बड़े-बड़े होर्डिंग में लगाने निर्देशित किया गया। सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वाले गुड सेमेरिटंस निम्नानुसार हैं-

दशरथ साहू पिता महरू राम साहू ग्राम बगदेहीपारा, नवापारा रायपुर द्वारा 12 दिसम्बर 2023 को बस स्टैण्ड नवापारा और 22 फरवरी 2024 को ग्राम पिपरौद चौक के पास हुए सड़क दुर्घटना में तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। खिलेश्वर महंत पिता फेरूदास महंत ग्राम भैसा ने 9 दिसम्बर 2023 को ग्राम कनकी के पास मो।सा। और पिकअप में हुए दुर्घटना में घायलों को तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर खरोरा हास्पिटल पहुंचाकर उनकी जान बचाई।

कार्तिक कुमार निर्मलकर पिता एन।नागराजन हाउसिंग बोर्ड कालोनी सेजबहार रायपुर ने दिनांक 11 फरवरी 2024 को डुण्डा नाला के पास एक कार अल्टो अनियंत्रित होकर नाले में जा घुसा था, जिसमें चालक व सवार व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसे तत्काल क्रेन वाहन उपलब्ध कर बाहर निकालकर तत्काल 108 एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल बुलाकर चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया गया।

दुनियाभर में उम्रदराज नेताओं का राज

नीरज कुमार दुबे

क्या दुनिया में शक्तिशाली नेता बनने के लिए 70 साल की उम्र अब कोई नया पैमाना होती जा रही है? यह सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि दुनिया के बड़े और ताकतवर देशों के हुक्मरानों को देखेंगे तो पाएंगे कि सब 70 या उससे ज्यादा वर्ष की उम्र के हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल के हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रिबेलो डिसूजा 75 साल के हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 70 साल के हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 71 साल के हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन 81 साल के हैं। आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल ड हिग्गिंस 82 साल के हैं। सऊदी अरब के किंग सलमान बिन अब्दुल्लाअजीज अल सउद 88 साल के हैं। इसी प्रकार कुछ और देशों में शासन संभाल रहे लोगों की उम्र को देखें तो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 76 साल की हैं। माल्टा के राष्ट्रपति जॉर्ज वेल्ला 81 साल के हैं। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासेन क्वाटरा 81 साल के हैं। जिम्माब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मनानगावा 81 साल के हैं। ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई 84 साल के हैं। गुएना के राष्ट्रपति अल्फा कोन्डे 86 साल के हैं। फिलस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास 88 साल के हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 72 साल के हैं। अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देलमादजिद टेबोन 78 साल के हैं। घाना के राष्ट्रपति नाना अकुफो अड्डु 79 साल के हैं और केमरून के राष्ट्रपति पॉल बिया 91 साल के हैं। वैसे वैश्विक स्तर पर जिस तरह सत्ता के गलियारों में उम्रदराज लोग राज कर रहे हैं यदि उसके कारणों पर गौर करें तो वह हर देश के हिसाब से अलग-अलग हैं। चीन में राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी कम्युनिस्ट पार्टी पर पूरा नियंत्रण रखा हुआ है और अपने मन मुताबिक वह चीनी संविधान में परिवर्तन करते रहते हैं। लगातार तीसरी बार वह राष्ट्रपति भी इसलिए बन पाये हैं क्योंकि उन्होंने दबाव बनाकर नियमों में संशोधन करवा लिया और संभव है जब तक जियेंगे तब तक वह चीनी राष्ट्रपति बने रहेंगे। इसी प्रकार यदि रूस को देखें तो वहां भी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लगातार सत्ता पर इसलिए काबिज हैं क्योंकि वह लोकतंत्र को अपने हिसाब से चला रहे हैं। जब उन्होंने रूस की सत्ता संभाली थी तब उनकी उम्र 47 थी मगर आज वह 71 की उम्र में भी लगातार रूस की सत्ता के सर्वोच्च केंद्र बने हुए हैं। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो वहां के दो दलीय राजनीतिक सिस्टम में युवाओं को अक्सर बिल्कुल नीचे से शुरुआत करनी होती है। अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए पार्टी की उम्मीदवारी हासिल करने के लिए चूंकि विभिन्न प्राइमरी चुनाव जीतने होते हैं और उसके लिए साधन संपन्नता, लोकप्रियता और नेटवर्किंग की आवश्यकता होती है इसलिए यह सब हासिल करते करते युवा नेता उम्रदराज हो जाते हैं। हाल के समय में सिर्फ बराक ओबामा ही थे जोकि 52 की उम्र में व्हाइट हाउस पहुँच गये थे। अमेरिका में अगला राष्ट्रपति चुनाव भी उम्रदराज नेताओं- जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच होना तय है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमेनुएल मैक्रों 39 साल की उम्र में देश के राष्ट्रपति बन गये थे। इसी तरह अगर आप ब्रिटेन में देखेंगे तो वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक 43 साल के हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी जब अपने देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं थीं तो उनकी उम्र 45 थी। इसी प्रकार यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदमीर जेलेंस्की की उम्र 46 साल है। बहरहाल, देखा जाये तो उम्र महज एक नंबर है। नेतृत्व करने वाले व्यक्ति की इच्छाशक्ति, प्रतिबद्धता और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता जैसे तत्व ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। इस संबंध में उदाहरण की बात करें तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में यह सभी गुण नजर आते हैं। वह लोकतंत्र को मजबूत रखते हुए जिस तरह विभिन्न विचारों को साथ लेकर चल रहे हैं वह अभूतपूर्व है। भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने के संकल्प को सिद्ध करने की राह पर आगे बढ़ने के साथ-साथ दुनिया के गरीब देशों की मदद करते रहने और जरूरत पड़ने पर विकसित देशों को आईना दिखाने तथा उनका मार्गदर्शन करने का भी कार्य जिस प्रकार मोदी कर रहे हैं उसके चलते वह वैश्विक नेताओं की ग्लोबल अप्रुवल रेटिंग में लंबे समय से शीर्ष पर बने हुए हैं।

सीएए पर केजरीवाल की बौखलाहट

ललित गर्ग

दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के लागू होने का बेहूदा, बेतुका एवं उच्छृंखल विरोध कर रहे हैं। वे एवं अन्य विपक्षी दलों के नेता सीएए रूपी उजालों पर कालिख पोतने का प्रयास करते हुए आकाश में पैबन्द लगाना चाहते हैं और सछिद्र नाव में सवार होकर राजनीति-सागर की यात्रा करना चाहते हैं। ऐसा करते हुए वे न केवल आम जनता को गुमराह कर रहे हैं, बल्कि अराजकता का माहौल निर्मित कर रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में लाखों की संख्या में पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से हिंदू व सिख आने से चोरी, रेप और अपराध की घटनाएं बढ़ने की बात कहकर केजरीवाल ने इन लोगों की भावनाओं को आहत किया हैं। केजरीवाल के बयान भ्रामक, बेबुनियाद एवं विध्वंसात्मक इसलिये है कि सीएए नये आने वाले हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध एवं पारसी लोगों पर लागू ही नहीं होगा, बल्कि देश में वर्ष 2014 एवं उससे पहले आये ऐसे शरणार्थियों को सीएए के अन्तर्गत नागरिकता देने का कानून हैं। अब इससे नये लोगों के आने, बेरोजगारी बढ़ने एवं कानून-व्यवस्था चरमरा के प्रश्न कहां से आ गये? विपक्षी दल इस कानून के सन्दर्भ में कपट और झूठ का सहारा लेकर जिस तरह दुष्प्रचार में जुट गए हैं, वह केवल अप्रत्याशित ही नहीं, खतरनाक भी है। वोट बैंक की बेहद सस्ती, घटिया और गंदी राजनीति के चलते किया जा रहा यह खतरनाक एवं देश तोड़क दुष्प्रचार न केवल लोगों को बरगलाने, बल्कि उकसाने वाला भी है। इस तरह का विरोध समय एवं शक्ति का अपव्यय है तथा बुद्धि का दिवालियापन है। यह लोकतंत्र के मूल्यों को धुंधलाने एवं ध्वस्त करने की कुचेष्टा है।

सीएए की मूल आत्मा को समझे बिना उसका विरोध करना एवं मोदी सरकार पर कीचड़ उछालना बौखलाहट का द्योतक हैं। केजरीवाल का यह कहना कि सीएए के साथ, भाजपा सरकार ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से बड़ी संख्या में गरीब अल्पसंख्यकों के भारत आने के गेट खोल दिए हैं। यह 1947 से भी बड़ा माइग्रेशन होगा। क्या केजरीवाल ने सीएए का नया कानून पढ़ा है, उसमें कहीं भी ऐसी किसी स्थिति का उल्लेख है? केजरीवाल की ही तर्ज पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को यह तो समझ नहीं आया कि नागरिकता कानून वैध है या नहीं, लेकिन उन्होंने यह ठान लिया कि वह बंगाल में उसे लागू नहीं होने देंगी। आखिर वह होती कौन हैं इस कानून को न लागू करने वाली? यह प्रश्न इसलिए, क्योंकि इस कानून का किसी राज्य सरकार से कोई लेना-देना ही नहीं। नागरिकता देना केवल केंद्र सरकार का अधिकार है। यह बुनियादी बात तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को भी समझनी होगी, क्योंकि उनकी ओर से भी यह कहा जा रहा है कि वह इस कानून को अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। यह हास्यास्पद एवं विरोधीभासी स्थिति है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस विचित्र नतीजे पर पहुंच गए कि नागरिकता कानून को अमल में लाकर केंद्र सरकार पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के लोगों को भारत लाकर उन्हें नौकरियां देने और उनके लिए घर बनाने का काम करने जा रही है। जबकि सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान एवं बांग्लादेश से किन्हीं नये अल्पसंख्यकों का भारत लाकर बसाने, उन्हें घर एवं नौकरी देने का कानून है ही नहीं। कोई भी यह समझ सकता है कि वह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से नागरिकता कानून की मनमानी व्याख्या कर रहे हैं और इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि यह कानून उक्त तीन देशों के अल्पसंख्यकों को बुलाकर नागरिकता देने का नहीं है।

केजरीवाल के बचकाने एवं बेहूदे बयानों से हिन्दू एवं सिख शरणार्थियों में काफी गुस्सा देखा गया है। उन पर चोरी, रेप और अपराध जैसे आधारहीन आरोप लगाने से उनकी भावनाएं आहत हुई हैं, जो शरणार्थी वर्षों से न्याय होने की उम्मीद लगाये इस कानून की प्रतीक्षा कर रहे थे, उन पर घटिया राजनीति के चलते तरह-तरह के वार उनको पीड़ा दे रहे हैं। केजरीवाल, ममता एवं एमके स्टालिन का मोदी-विरोध के नाम पर देश-विरोध एवं कानून विरोध पर उतर जाना उनकी स्तरहीन राजनीति को ही दर्शा रहा है। मोदी का विरोध कोई नई बात नहीं है। कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होने लगता है कि इन नेताओं की विरोध करना ही नियति हैं। आश्चर्य इस बात का है कि विरोध की तीव्रता एवं दीर्घता के बावजूद मोदी के अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आ सकी। जहां तक सीएए के लागू होने का प्रश्न है तो यह अब एक कानून बन चुका है और उसे लागू होने से कोई नहीं रोक सकता।

दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को पाकिस्तान, बांगलादेश और अफगानिस्तान से आये हिंदू व सिख शरणार्थियों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, उनकी दीन दशा से परिचित होने के साथ ही उनके प्रति न्यूनतम संवेदनशीलता का भी उन्हें परिचय देना चाहिए। यदि विरोधी दलों को यह लगता है कि नागरिकता कानून ठीक नहीं तो वह उससे असहमति जताने और कांग्रेस एवं तृणमूल कांग्रेस नेताओं की तरह सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को स्वतंत्र हैं, लेकिन इसके नाम पर उन्हें लोगों को भड़काने से बाज आना चाहिए। उनकी इसी भड़काऊ राजनीति के कारण चार साल पहले देश में जगह-जगह हिंसा हुई थी और शांतिपूर्ण विरोध के बहाने आगजनी की गई थी। दिल्ली में तो शाहीन बाग इलाके में विपक्षी दलों के सहयोग और समर्थन से एक व्यस्त सड़क घेरकर महीनों तक धरना चलाने से आम जनता पीड़ित एवं परेशान हुई। विद्वेष और वैमनस्य पैदा करने वाले इसी धरने के चलते दिल्ली में भीषण दंगा हुआ था, जिसमें 50 से अधिक लोग मारे गए थे। क्या विपक्षी दल अशांति, हिंसा एवं अराजकता की आग फैलाकर फिर से अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं? यदि नहीं तो फिर उन्हें नागरिकता कानून के विरोध में जबान संभालकर बोलना चाहिए। विरोध का भी कोई उद्देश्य और स्तर होता है। निरुद्देश्य एवं स्तरहीन विरोध, विरोधी खेमे की स्वार्थपूर्ण मनोवृत्ति, ईर्ष्या एवं विध्वंस की नीति का ही स्वयंभू प्रमाण है।

सीएए लागू होने को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीति तेज होने लगी है, यह आगामी लोकसभा चुनाव का एक मुख्य मुद्दा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भाजपा नेता इसे नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा उठाया गया ऐतिहासिक कदम बता रहे हैं तो वहीं विपक्ष इसका विरोध कर रहा है। लेकिन मोदी सरकार का यह कदम ऐतिहासिक एवं साहसिक तो है, क्योंकि आजादी के बाद से अब तक शरणार्थियों ने जो तकलीफें झेली हैं, जो कष्ट एवं उपेक्षाओं का जीया है, वह उन्हें नागरिकता मिलने से ही दूर हो सकती है। अब उन्हें नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो गया है तो उसका स्वागत होना चाहिए। केजरीवाल तो शरणार्थियों को मिल रही नागरिकता की स्वतंत्र सांसों का स्वागत की बजाय विरोध कर रहे हैं, यह कैसी राजनीति है? यह कैसे राजनेता है? यह कैसा राजनीतिक चरित्र है? केजरीवाल एवं ममता की मानें तो सीएए लागू होने के बाद अगर पड़ोसी देशों के डेढ़ करोड़ अल्पसंख्यक भी भारत आ गए तो यह स्थिति 'खतरनाक' हो जाएगी।' कोई उनसे पूछे कि इस कानून में ऐसा कहा लिखा है? यह गन्दी गैर-जिम्मेदाराना राजनीति का द्योतक है, जिसका जबाव आम-जनता आगामी लोकसभा चुनाव में देगी। इन नेताओं ने मोदी के खिलाफ एवं राष्ट्रहीत की नीतियों एवं योजनाओं पर कीचड़ उछालने की जो हरकतें की हैं, सीएए तक पहुंच कर वे पराकाष्ठा तक पहुंच गयी हैं। पर इससे मोदी का वर्चस्व कभी धूमिल होने वाला नहीं हैं। क्योंकि उनकी नीति विशुद्ध है और सैद्धान्तिक आधार पुष्ट है। विरोध करने वाले नेता स्वयं इस बात को महसूस करते हुए बौखलाये हुए हैं। अपनी बौखलाहट एवं सरकती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिये वे जनता को गुमराह करने के लिये और उनका मनोबल कमजोर करने के लिये सीएए रूपी उजालों पर कालिख पोत रहे हैं, वे धूर्त तथ्यों से विपरीत जाकर अनर्गल प्रलाप कर रहे है, इससे उन्हीं के हाथ काले होने की संभावनाएं हैं। ऐसे नासमझ नेताओं को सद्बुद्धि आए, वे अपना समय एवं श्रम स्वस्थ एवं आदर्श राजनीति में लगाएं तो लोकतंत्र भी मजबूत होगा एवं जनता को भी विकास की नयी दिशाएं दिखाई देगी।

भारतीय ज्ञान परंपरा....

महोपनिषद् (भाग-34)

गतांक से आगे...

हे मुने ! इस प्रकार के विकार-रहित मन के द्वारा इस विशाल बन्धनरूपी जाल को विनष्ट कर दो। स्वयमेव संसार-सागर से पार हो जाओ। अन्य और किसी के द्वारा यह संसार रूप सागर नहीं पार किया जा सकता। जब-जब अन्त:करण को आच्छादित करने वाली मनरूपी वासना का प्राकट्य हो, तब-तब उसका परित्याग करना ज्ञानी मनुष्य का परम कर्तव्य हो जाता है, क्योंकि ऐसा करने से अविद्या का विनाश हो जाता है।

सर्वप्रथम भोगरूपी वासना का त्याग करो, फिर भेदरूपी वासना का त्याग करो, उसके पश्चात् भाव-अभाव दोनों का ही त्याग करके निर्विकल्प होकर पूर्ण सुखी हो जाओ। मन का विनाश ही अविद्या का विनाश कहा गया है। मन द्वारा जो कुछ भी अनुभूति में आता हो, उस-उसमें आस्था कदापि न होने दो। आस्था का परित्याग करना ही निर्वाण है और आस्था के आश्रित रहना ही दु:ख है। जो प्रज्ञा से रहित है, उन्हीं में अविद्या प्रतिष्ठित रहती है। सम्यक् प्रज्ञासम्पन्न मनुष्य नाम मात्र के लिए भी कहीं अविद्या को स्वीकार नहीं करते। इस दु:खरूपी कंटक से ओत-प्रोत संसार रूपी भ्रमजाल में तभी तक अविद्या अपने साथ देहधारी को निरन्तर भ्रमाती है, जब तक इसको विनष्ट करने वाली मोहनाशिनी आत्मसाक्षात्कार की आकांक्षा स्वयं ही उत्पन्न नहीं होती। यह अविद्या जब परमात्मतत्त्व की ओर देखती है, तब इसका स्वयं ही नाश हो जाता है। सर्वात्मबोध के दर्शन होते ही अविद्या स्वयं ही लुप्त हो जाती है। केवल इच्छा मात्र ही अविद्या का स्वरूप है और इच्छा का पूरी तरह से नष्ट होना ही मोक्ष कहा गया है। हे मुने ! किन्तु इच्छा तभी समाप्त होती है, जब संकल्प का पूर्णरूपेण विनाश हो जाये, अन्यथा इच्छा का नाश असम्भव है। चित् रूपी सूर्य के प्रकाश से कलिरूपी अन्धकार क्षीण हो जाता है।

क्रमश: ...

अंतरिक्ष पर जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला

शिवानी अवस्थी

विश्व की महिलाएं धरती से आसमान तक अपने हुनर, काबिलियत का परचम लहरा रही हैं। भारतीय महिलाओं की बात करें तो राजनीति से लेकर औद्योगिक क्षेत्र तक, कला क्षेत्र से लेकर खेल जगत जगत तक हर क्षेत्र में दमदार भूमिका में हैं। वर्तमान में महिलाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देने में इतिहास की कुछ दमदार महिलाओं की भूमिका अहम रही। आज हम चांद और मंगल ग्रह पर रहने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अंतरिक्ष में रहने के सपने दिखाने वालों में एक भारतीय मूल की एक महिला भी शामिल है। इस महिला का नाम कल्पना चावला है। कल्पना चावला पहली भारतीय मूल की महिला थीं, जिन्होंने अंतरिक्ष तक का सफर तय किया था। उनकी इस उपलब्धि से महज महिलाओं को प्रेरणा नहीं मिली, बल्कि भारत के लिए गौरव और विश्व के लिए ऐतिहासिक पल बन गया।

हरियाणा के करनाल में 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला था और माता संज्योती चावला थीं। कल्पना सबसे छोटी थीं। उनकी शुरुआती शिक्षा करनाल में ही टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हुई।

कल्पना चावला का बचपन से ही पसंदीदा विषय विज्ञान रहा था। वह एक फ्लाइट इंजीनियर बनना चाहती थीं। इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। इस दौरान उन्हें नौकरी के ऑफर भी मिले। लेकिन वह आगे की पढ़ाई के लिए महज 20 साल की उम्र में अमेरिका चली गईं।

अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में कल्पना ने दाखिला लिया और दो साल की पढ़ाई के बाद एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री हासिल की। उन्होंने वर्ष 1986 में दूसरी मास्टर्स डिग्री हासिल की। बाद में 1988 में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी कर लिया। अब तक कल्पना ने तय कर लिया था कि उन्हें अंतरिक्ष पर जाना है। उनके पास अब कमर्शियल पायलट का लाइसेंस भी था और कल्पना एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर बन चुकी थीं। इस दौरान उन्होंने फ्रांस के जान पियरे से शादी कर ली, जो खुद एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे।

वर्ष 1993 में कल्पना चावला ने पहली बार नासा के लिए अप्लाई किया लेकिन उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। 1995 में नासा ने कल्पना का चयन अंतरिक्ष यात्री के तौर पर किया। उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई और 1998 में अंतरिक्ष की पहली उड़ान के लिए कल्पना चावला को चुना गया। अपनी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कल्पना चावला ने 372 घंटे बिताते हुए इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया और भारत का मान बढ़ाया। 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला का निधन तब हुआ जब कोलंबिया स्पेस शटल उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और यान में सवार सभी अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई।

अविश्वास और आत्मविश्वास के बीच खड़े दल

अमिताभ श्रीवास्तव

लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के समय के नजदीक आते ही राजनीतिक दलों ने संयम तोड़ना आरंभ कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने तो सीटों के बंटवारे के पहले विधिवत अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, जबकि शरद पवार नीत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) हो या फिर उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना, दोनों दलों ने मंचों और बैठकों से अपने उम्मीदवार घोषित करने आरंभ कर दिए हैं। यह सिद्ध करता है कि गठबंधन चाहे किसी भी दल के साथ हो, पहले अपनी चिंता का मंत्र सर्वोपरि है। यह नौबत इसलिए भी है कि हर गठबंधन टूट-फूट से बना है। उसमें जितनी बाहरी मजबूती है, उतना ही भीतरी खोखलापन भी है। उनमें जितना आपसी भरोसा है, उतने ही एक-दूसरे के साथ शक और सवाल भी हैं।

पिछले कुछ दिनों से शिवसेना उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे अपनी जनसभाओं और मेल-मुलाकात के बाद लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की घोषणा करते जा रहे है, जिससे उनके गठबंधन के सहयोगी दलों में बेचैनी है किंतु वह बेपरवाह हैं। ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के दूसरे घटक राकांपा ने अपने दो उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। किंतु दोनों के तेज चलने पर गठबंधन का तीसरा घटक कांग्रेस परेशान है। हालांकि तीनों दलों के बीच अभी तक औपचारिक गठबंधन की घोषणा भी नहीं हुई है। साथ ही लंबे समय से प्रतीक्षारत वंचित बहुजन आघाड़ी को साथ लेने पर कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ है। फिर भी छत्रपति संभाजीनगर में वंचित बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर औरंगाबाद लोकसभा सीट पर अपना दावा ठोंकते हैं, जबकि उनके दावे के एक दिन पहले ही शिवसेना (उद्धव

ठाकरे) के संभावित उम्मीदवार पूर्व सांसद चंद्रकांत खैरे अपने चुनाव प्रचार कार्यालय का भूमिपूजन करते हैं।

दूसरी तरफ भाजपा ने अपने 20 अधिकृत उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन शिवसेना (शिंदे गुट) के साथ तालमेल की घोषणा नहीं हुई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के औरंगाबाद लोकसभा सीट के रूप में एक कमल का फूल भेजने की अपील के बावजूद शिवसेना (शिंदे गुट) के नेता और छत्रपति संभाजीनगर जिले के पालक मंत्री संदीपान भुमरे पहले सीट छोड़ने की बात करते हैं और कुछ ही दिन में उनके ही एक नेता भुमरे के ही औरंगाबाद से चुनाव लड़ने की संभावना को जता देते हैं। दोनों के अलावा महागठबंधन में राकांपा के अजित पवार गुट की महत्वाकांक्षा हिलोरें ले रही है। वह समझौते की मनःस्थिति में नहीं हैं। भाजपा तीस से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त कर रही है, जबकि बीस उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में राकांपा ने 19 सीटों पर चुनाव लड़ते हुए चार सीटें जीती थीं। तब वह कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। इसी प्रकार शिवसेना ने भाजपा के साथ तालमेल कर 23 सीटों पर चुनाव लड़कर 18 पर विजय पाई थी। वहीं भाजपा 25 सीटों पर चुनाव लड़कर 23 सीटें जीत गई थी। इस हिसाब से भाजपा 'स्ट्राइक रेट' अच्छा मानकर अधिकतम सीटों पर लड़ना चाह रही है, जबकि बाकी दल जीत से ज्यादा पिछले चुनाव में लड़ी सीटों के आधार से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं।

पिछले चुनाव के हिसाब से भाजपा ने 27.8 प्रतिशत मत हासिल किए थे, जबकि शिवसेना ने 23.5 प्रतिशत वोट लिए थे. इसी प्रकार गठबंधन में कांग्रेस ने 16.4 प्रतिशत और राकांपा ने 15.6 प्रतिशत मत प्राप्त किए थे। वंचित बहुजन आघाड़ी 6.98 प्रतिशत और स्वाभिमान पक्ष 1.55 प्रतिशत मत हासिल कर सके थे। यद्यपि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) ने एक सीट जीती, किंतु उसे 0.72 प्रतिशत मत ही मिले थे। बहुजन समाज पार्टी (0.86 प्रतिशत) और बहुजन विकास आघाड़ी (0.91 प्रतिशत) जैसे कुछ दल सीटें नहीं जीतने के बावजूद मत पाने में सफल थे। अब भाजपा और कांग्रेस को छोड़ सभी दलों में बिखराव की स्थिति है। चुनाव के पहले मतदाताओं की प्रतिबद्धता पर भरोसा करना किसी भी दल के लिए संभव नहीं हो पा रहा है। इसी के बीच हर दल का अपना आकलन और अपनी तैयारी है। यहीं दूसरों के प्रति अविश्वास और स्वयं के प्रति आत्मविश्वास जन्म ले रहा है। खास तौर पर टूटने के बाद बिखरे दलों के बीच आत्मविश्वास दिखाना भी एक मजबूरी है, क्योंकि उसके सहारे ही मतदाता का विश्वास जीता जा सकता है। किंतु इस दिखावे में मजबूरी यह कि पिछली बार 23 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली शिवसेना और 19 सीटों पर चुनाव लड़ने वाली राकांपा के पास नए गठबंधन में इस बार आधी सीटें भी लड़ने का अवसर नहीं है, जिससे उन्हें अपनी घटती राजनीतिक हैसियत का अहसास हो रहा है। यदि यह बात मतदाता के मन में घर कर गई तो यही नहीं, अगले विधानसभा चुनाव में भी मजबूरी में ही चुनाव लड़ना होगा. इसलिए जरूरी यही है कि अभी से मोल-तोल में कम या कमजोर न रहा जाए।

दरअसल चुनाव की बिसात पर आकांक्षा, महत्वाकांक्षा, विश्वास और अविश्वास से अधिक जीत के आत्मविश्वास की आवश्यकता होती है। नए दौर में इसे अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए राजनीतिक दलों ने सर्वेक्षणों का भी सहारा लेना आरंभ कर दिया है। इस स्थिति में परस्पर मुकाबलों की अधिक गुंजाइश नहीं रह जाती है। वास्तविकता के धरातल पर चल कर चुनाव लड़ने का फैसला किया जा सकता है। 'अबकी बार चार सौ पार' का चक्कर हो या फिर दल के टूटने के बाद की असलियत साबित करने का मौका हो, मतदाता के मन में दल और उम्मीदवार के प्रति स्पष्टता होती ही है। इसके लिए सार्वजनिक प्रपंच से अधिक जरूरी चुनाव की ठोस तैयारी है, जिसे किसी पर अविश्वास और स्वयं पर आत्मविश्वास के साथ नहीं जीता जा सकता है। शायद देर-सबेर राजनीतिक दलों को यह बात समझ में आएगी। फिलहाल निष्ठा और प्रतिष्ठा के संघर्ष में इस बात पर ध्यान देने का समय शायद न मिले।

आज का इतिहास

1722 विलियम केएच फिसो को डेरेन का महापौर नियुक्त किया गया।
1756 सेंट पैट्रिक दिवस पहली बार न्यूयॉर्क शहर में मनाया गया।
1762 न्यूयॉर्क शहर में पहली सेंट पैट्रिक दिवस परेड आयोजित की गयी।
1776 अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध-बोस्टन में मैसाचुसेट्स में ब्रिटिश सेना का कब्जा, शहर से हट गया, बोस्टन के 11 महीने के घेराबंदी को समाप्त कर दिया।
1824 1824 की एंग्लो-डच संधि पर हस्ताक्षर किए गए।
1860 प्रथम तारानाकी युद्ध न्यूजीलैंड के वेटारा में शुरू हुआ, जो न्यूजीलैंड भूमि युद्धों का महत्वपूर्ण चरण था।
1891 ट्रान्साटलांटिक स्टीमशिप एसएस यूटोपिया ने गलती से जिब्राल्टर की खाड़ी में युद्धपोत एचएमएस एनसन को टक्कर दे दी, बीस मिनट में डूब गया और 562 की मौत हो गई।
1906 ताइवान में आए भूकंप में तकरीबन 1200 लोगों की मौत हो गई।
1943 विलेम जे कोल्फ ने कृत्रिम गुर्दे की मशीन का उपयोग कर विश्व का पहला हेमोडायलिसिस किया था जो कि असफल रहा।
1950 कैलीफोर्नियम के संश्लेषण, एक रेडियोधर्मी ट्रांसूरानियम तत्व की घोषणा की गई थी।
1955 मॉन्ट्रियल में छह हजार लोगों ने आइस हॉकी स्टार मौरिस रिचर्ड के प्रतिवाद का विरोध करने के लिए दंगा किया।
1957 माउंट मनुंगल के ढलान पर एक विमान दुर्घटना ने फिलीपाइनसर्पिडेंट रेमन मैग्सेसे और 24 अन्य को मार डाला।
1958 संयुक्त राज्य अमेरिका के वैनगार्ड 1 उपग्रह को प्रक्षेपित किया।
1963 इंडोनेशिया के बाली पर माउंट अगुंग के सबसे हालिया विस्फोट में लगभग 1,500 लोग मारे गए।
1973 स्लाव वेदेर ने अपने पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटोग्राफ बर्स्ट ऑफ जोजॉय को लिया, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंत में वियतनाम युद्ध में शामिल होने का प्रतीक था।
1991 नौ सोवियत गणराज्यों में लगभग 70% मतदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि सोवियत संघ के जनमत संग्रह में सोवियत संघ को संरक्षित किया जाना चाहिए।

किस आधार पर भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति नामों को देती है मंजूरी?

नीरज कुमार दुबे

लोकसभा चुनावों से पहले भाजपा अबकी बार 400 पार का नारा लगा रही है। यह नारा हकीकत बनता है या नहीं यह तो चुनाव परिणाम बाद ही पता चलेगा लेकिन इतना तो है कि चुनावी तैयारियों के लिहाज से भाजपा इस समय अन्य दलों से काफी आगे नजर आ रही है। आम चुनावों की तारीखों की घोषणा से पहले भाजपा अपने उम्मीदवारों की दो सूची जारी कर चुकी है। इस दौरान देखने को मिला कि सिर्फ मीडिया ही नहीं बल्कि जनता भी भाजपा उम्मीदवारों की सूची में शामिल नामों को जानने के लिए उत्सुक थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि भाजपा की उम्मीदवारी हासिल करना ही जीत की गारंटी है। शायद इसी गारंटी के लालच में ही चुनावों से पहले कई नेताओं ने दल बदल कर भाजपा का दामन थाम लिया तो कई ऐसे नेता भाजपा में लौट आये जोकि कुछ समय पहले कहीं और चले गये थे।

चुनावों से पहले जिस तरह भाजपा से लोकसभा चुनाव का टिकट हासिल करने के लिए होड़ दिखी वह अभूतपूर्व थी। हमने भाजपा के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में कई ऐसे लोगों को भी पाया जोकि भाजपा से जुड़े हुए नहीं थे लेकिन वहां इसलिए आ गये थे ताकि पार्टी नेताओं को देश के लिए काम करने के अपने विजन के बारे में बता कर उम्मीदवारी हासिल कर सकें। इन लोगों का विश्वास था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में भाजपा का टिकट हासिल करने के लिए वरिष्ठ नेताओं की परिक्रमा करनी जरूरी नहीं है और अब सिर्फ योग्यता के आधार पर ही किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है। देखा जाये तो यह लोग कुछ हद तक सही भी थे लेकिन भाजपा के काम करने के तरीके से अनजान थे इसलिए जब वह सीधे लोकसभा चुनाव का टिकट मांग रहे थे तो वहां खड़े लोग मुस्कुरा रहे थे।

इसलिए आइये आपको समझाते हैं कि भाजपा आखिर किस आधार पर किसी को पार्टी का उम्मीदवार बनाती है। सबसे पहले तो आपको यह समझना होगा कि भाजपा चुनावों से ठीक पहले या चुनावों की घोषणा के बाद ही उम्मीदवारों की तलाश शुरू नहीं करती है बल्कि उसकी यह प्रक्रिया सतत रूप से चलती रहती है। मसलन जैसे अभी लोकसभा चुनाव होने हैं तो उसके लिए उम्मीदवारों के नामों पर मंथन डेढ़ साल से चल रहा है। अभी भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की जो दो बैठकें हुई हैं उनमें सिर्फ उन नामों पर मुहर लगाने का काम हुआ है जोकि पार्टी की विभिन्न समितियों ने केंद्रीय चुनाव समिति को तमाम तरह की रिपोर्टों के साथ संलग्न करके भेजे थे।

हमारे पास सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं उसके मुताबिक आइये आपको समझाते हैं जब भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होती है तो उसमें क्या होता है। उदाहरण के लिए लोकसभा चुनावों की ही बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति वाली बैठक में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्यों को सबसे पहले यह बताते हैं कि आज किन राज्यों की सीटों पर चर्चा होनी है। इसके बाद उस राज्य से भाजपा मुख्यालय में पहले से आकर बैठे हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या विधायक दल का नेता, राज्य के पार्टी प्रभारी और यदि किसी केंद्रीय मंत्री के पास उस राज्य का प्रभार है तो उनको भी बैठक में बुला लिया जाता है। मान लीजिये कि उस राज्य में 25 सीटें हैं। सबसे पहले उन सीटों पर चर्चा की जाती है जहां किसी को फिर से मौका देना है।

प्रदेश अध्यक्ष एक-एक कर सीट का नाम बोलते हैं और बैठक कक्ष में मौजूद बड़ी स्क्रीन पर उस सीट के दावेदारों का परिचय फोटो के साथ एक-एक करके आता रहता है। सभी दावेदारों के आगे विभिन्न सर्वेक्षणों की रिपोर्ट के अलावा यह भी लिखा होता है कि उन्होंने पार्टी के कार्यों में कितनी रुचि दिखाई, विवादों में कितना घिरे रहे, संसदीय कार्यों में कितनी रुचि ली, संसद में कितनी उपस्थिति रही, सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों को जनता तक पहुँचाने के अभियान में क्या योगदान दिया, स्थानीय स्तर पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ कैसा व्यवहार रहा, संसदीय क्षेत्र में जो वादे किये थे उन्हें कितना पूरा किया। इसके अलावा उस क्षेत्र के राजनीतिक और सामाजिक समीकरणों से संबंधित ग्राफ के अलावा उस सीट पर विपक्ष की ओर से खड़ी की जाने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जाती है। राज्य के नेता एक-एक करके हर दावेदार के नाम के गुण और दोष बताते हैं। उसके बाद भाजपा संगठन के राष्ट्रीय महासचिव उन एजेंसियों की सर्वेक्षण रिपोर्ट दिखाते हैं जो भाजपा ने उस क्षेत्र के संभावित प्रत्याशियों को लेकर करवायी होती है। वह यह भी बताते हैं आरएसएस और उसके आनुषांगिक संगठनों की ओर से उस क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए क्या फीडबैक मिला है। इसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति के सदस्य उन नामों पर अपनी राय रखते हैं और जो नाम तय होते जाते हैं उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति के सचिव अलग से नोट करते रहते हैं। जिन नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति का कोई सदस्य या खुद प्रधानमंत्री उस पर आपत्ति जता दें तो फिर पार्टी की प्रदेश इकाई को उस सीट के लिए और नाम सुझाने के लिए कहा जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि नामों पर चर्चा करने के लिए आई प्रदेश इकाई टीम को कह दिया जाता है कि किसी भी निवर्तमान सांसद या पहले लड़ चुके उम्मीदवार को इस बार मौका नहीं दिया जायेगा इसलिए सभी नाम नये होने चाहिए।

इसी तरह एक के बाद एक अलग राज्यों के नेताओं को बुला कर चर्चा की जाती है। मान लीजिये कि एक दिन में चार राज्यों पर चर्चा हुई तो उन चार राज्यों की जिन सीटों के लिए नाम तय हो गये हैं उसे जारी करने से पहले एक बार फिर से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिखाया जाता है और फिर मीडिया को नाम जारी कर दिये जाते हैं। हम आपको यह भी बता दें कि पार्टी की राज्यों की चुनाव समिति केंद्रीय चुनाव समिति में नाम भेजने से पहले सभी दावेदारों की सूची बनाती है। इस सूची में वह नाम तो होते ही हैं जो दावेदारों ने खुद आवेदन करके दिये होते हैं साथ ही इसमें वह नाम भी होते हैं जो भाजपा की स्थानीय इकाई, संघ और उसके आनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारियों की ओर से भेजे गये होते हैं। इसके अलावा राज्यों में भाजपा के संगठन महासचिव या पूर्णकालिक कार्यकर्ता हमेशा इस बात की खोज करते रहते हैं कि समाज जीवन के जिस भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति उल्लेखनीय कार्य कर रहा हो उसे कैसे पार्टी से जोड़ा जाये और समय आने पर उसे चुनाव लड़ने का अवसर भी दिया जाये, ऐसे में यदि वह कोई नाम सुझाते हैं तो उसे भी इस सूची में शामिल किया जाता है। इसलिए आपको भाजपा की सूची में कई बार विभिन्न क्षेत्रों के ऐसे प्रोफेशनल्स का नाम भी देखने को मिल जाता है जिन्होंने कभी टिकट के लिए आवेदन ही नहीं किया था। किसी राज्य के उम्मीदवारों को तय करते हुए यह भी ध्यान दिया जाता है कि वहां की सूची में अनुभवी नेताओं, युवाओं, महिलाओं, पार्टी के प्रति समर्पित कार्यकर्ताओं के साथ ही समाज के सभी वर्गों को पर्याप्त भागीदारी मिले।

भाजपा के टिकट के लिए एक और जरूरी बात यह है कि व्यक्ति पार्टी का सक्रिय सदस्य होना चाहिए। पार्टी की सामान्य सदस्यता तो सभी को मिल जाती है लेकिन सक्रिय सदस्यता हासिल करने के लिए कुछ अनिवार्यताएं हैं जिन्हें पूरा करना होता है। लेकिन अक्सर उन लोगों को इन अनिवार्यताओं से छूट मिल जाती है जो बड़े नेता होते हैं और दल बदल कर भाजपा में आते ही टिकट हासिल कर लेते हैं। ऐसे नेताओं को अक्सर आपने देखा होगा कि वह सामान्य सदस्यता वाली पर्ची मीडिया को दिखाते हुए खुद के भाजपा में शामिल होने की घोषणा करते हैं और अगले ही दिन या कुछ ही घंटों में उम्मीदवारी भी हासिल कर लेते हैं।

बहरहाल, भाजपा का टिकट हासिल करने की जो प्रक्रिया लोकसभा चुनाव में है वही विधानसभा और अन्य चुनावों में भी होती है। लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा और विधान परिषद के उम्मीदवारों को मंजूरी पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति देती है और नगर निगमों, नगर पालिकाओं और पंचायतों के उम्मीदवारों के नामों को उस प्रदेश की चुनाव समिति मंजूरी देती है।

कांग्रेस के राजनीतिक प्रबंधन पर उठते सवाल

राजकुमार सिंह

राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान भी कांग्रेस से पलायन थमता नहीं दिख रहा। दक्षिण भारत को अपवाद मान लें तो उत्तर से लेकर पूर्व और पश्चिम तक कांग्रेसियों में पार्टी का हाथ छोड़ने की होड़-सी मची है। घोषित कार्यक्रम के अनुसार राहुल की यात्रा 20 मार्च को मुंबई पहुंचेगी, लेकिन जारी भगदड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री मिलिंद देवड़ा से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण तक कई नेता कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। कारण अलग-अलग हो सकते हैं, पर मंजिल एक ही है- भाजपा और उसके मित्र दल। गुजरात में तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्ष के नेता रह चुके अर्जुन मोढवाडिया ने कांग्रेस का हाथ झटक दिया।

मोढवाडिया के अलावा पार्टी के दो पूर्व विधायक अंबरीश डेर और मुलूभाई कंडोरिया भी भाजपा में चले गए। विधानसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा देनेवाले मोढवाडिया ने कारण रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन से पार्टी की दूरी को बताया है, लेकिन फैसला लेने में उन्हें महीने से भी ज्यादा लग गया। अरुणाचल में तीन विधायक कांग्रेस का हाथ छोड़ चुके हैं। हाल ही में राजस्थान के दो पूर्व मंत्रियों, एक पूर्व सांसद और पांच पूर्व विधायकों ने हाथ छोड़ कर कमल थाम लिया। अनुभव बताता है कि जैसे-जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे, दल-बदल की रफ्तार और तेज हो सकती है। बेशक सत्ता केंद्रित राजनीति में विचार की जगह स्वार्थ ने ले ली है, लेकिन कांग्रेस जैसी भगदड़ अन्य दलों में नजर नहीं आती। इसलिए भी कि वरिष्ठ नेताओं के भी पलायन का अनुमान लगाने व उसे रोक पाने में कांग्रेस आलाकमान अक्सर नाकाम नजर आता है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में जो कुछ हुआ, उससे तो कांग्रेस के राजनीतिक प्रबंधन पर ही प्रश्नचिन्ह लग जाता है। अन्य राज्यों में भी सब कुछ सामान्य नहीं है। गुटबाजी कांग्रेस के राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रही है, पर आलाकमान और प्रादेशिक नेताओं के बीच ऐसी संवादहीनता कभी नहीं रही। ऐसा राजनीतिक प्रबंधन तंत्र भी हमेशा रहा, जो देश से लेकर प्रदेशों तक कांग्रेस नेताओं पर नजर रखता था, ताकि बीमारी गंभीर होने से पहले ही जरूरी उपचार किया जा सके। लगता है कि अहमद पटेल के निधन के बाद वैसा कोई राजनीतिक प्रबंधन तंत्र कांग्रेस में नहीं है। हाल यह है कि किसी एक मठाधीश के हवाले पूरे राज्य की राजनीति छोड़ दी जाती है- और बाकी नेता उसके रहमोकरम पर। ये मठाधीश अपनों के अलावा किसी और को पनपने नहीं देते। परिणामस्वरूप आलाकमान की भी उन पर निर्भरता लगातार बढ़ती जाती है। इससे संगठन तो खोखला हो ही रहा है, आलाकमान की कमान भी कमजोर पड़ रही है और क्षत्रप उसे आंखें दिखाने में संकोच नहीं करते। शायद कांग्रेस को भाजपा से कुछ सबक सीखने चाहिए जो शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे और रमन सिंह सरीखे क्षत्रपों को बदलने में संकोच नहीं करती- और जिसका आलाकमान अपने ही नहीं, दूसरे दलों के नेताओं से मुलाकात के लिए भी सहज सुलभ रहता है।

नागरिकता संशोधन कानून पर सियासत

विराग गुप्ता

संसद से पारित होने के अगले दिन 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) को मंजूरी दी थी। उसके साढ़े चार साल बाद लोकसभा चुनाव के पहले नियमों को नोटिफाइ करने से सियासी घमासान बढ़ गया है। संसद से पारित कानूनों को मंजूरी मिलने के बाद छह महीने के भीतर उनसे जुड़े नियमों को अधिसूचित करना चाहिए। लेकिन डाटा सुरक्षा जैसे कई कानूनों पर कई साल से नियम नहीं बने हैं। इसलिए यह दावा गलत है कि चुनाव के पहले नियम लागू नहीं करने पर नागरिकता कानून की वैधता खत्म हो जाती। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी धर्म के जो शरणार्थी 31 दिसंबर 2014 तक भारत आ गये हैं, उन्हें नये कानून के अनुसार नागरिकता मिल सकती है। भारत में निवास के प्रमाण के तौर पर बीस तरह के दस्तावेजों में से एक और पड़ोसी देश के निवास के प्रमाण के तौर पर नौ में से एक दस्तावेज को आवेदन के साथ लगाने की जरूरत है। संविधान में नागरिकता के बारे में कानून बनाने के लिए संसद और केंद्र सरकार को सभी अधिकार हासिल हैं।

जो लोग 26 जनवरी 1950 को भारत के अधिकार क्षेत्र में निवास करते थे या जिनका जन्म भारत में हुआ हो या जिनके माता-पिता में से कोई भारत का नागरिक हो, उन्हें भारत का नागरिक माना जाता है। गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सीएए का भारतीय मुसलमानों से लेना-देना नहीं है। यह कानून अवैध अप्रवासियों के निर्वासन से भी संबंधित नहीं है। पुराने कानूनों के अनुसार प्राकृतिक आधार पर किसी को भी नागरिकता दी जा सकती है, इसलिए मुसलमानों को भारत में नागरिकता हासिल करने पर कोई रोक नहीं है। साल 1955 में बनाये गये नागरिकता कानून के अनुसार नौ राज्यों के गृह सचिव और 30 से ज्यादा जिलाधिकारियों को नागरिकता देने के अधिकार हैं। उसके अनुसार पिछले चार सालों में गृह मंत्रालय को तीन देशों के शरणार्थियों से 8,244 आवेदन मिले, जिनमें से 3,117 अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता दी गयी। ऐसे में कई लोग नया कानून बनाने की जरूरत पर भी सवाल उठाते

हैं। भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक हिंदुओं का उत्पीड़न हो रहा है। संविधान में नागरिकता देने के लिए धर्म का आधार शामिल नहीं है, इसलिए विपक्ष शासित कई राज्यों के साथ अनेक नेता नये नियमों को विभाजनकारी और भेदभावपूर्ण बता रहे हैं। ओवैसी के अनुसार भारत में धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर नागरिकता का निर्धारण करना गलत और गैरकानूनी है। केरल की विधानसभा में इस कानून के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने के साथ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि इस कानून के तहत नागरिकता के आवेदन से लोग अवैध शरणार्थी बन सकते हैं। दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि एनआरसी में शामिल हुए बगैर अगर किसी को नागरिकता मिली, तो वे पद से त्यागपत्र दे देंगे। जेनेवा की अंतरराष्ट्रीय संधि का उल्लंघन बताते हुए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने इस कानून की आलोचना की है। पड़ोसी देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के बारे में भाजपा ने अपने घोषणापत्र में कई बार जिक्र किया था। मोदी सरकार ने 2014 में पहली बार इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था, लेकिन उसमें जैन और पारसी शामिल नहीं थे। साल 2016 में सरकार ने तीन देशों के छह धर्मों के अल्पसंख्यकों को भारत में रहने के लिए दीर्घकालिक वीजा के नियमों को मान्यता दी थी। नये कानून से ऐसे लोगों को भारत की स्थायी नागरिकता जल्दी मिल सकेगी।

सीएए को एनआरसी के साथ जोड़ने और चुनावी भाषणों में उनके जिक्र की वजह से बहुत गलतफहमियां हो रही हैं। साल 2003 में जनगणना कानून के तहत राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) के लिए कानून बना था। फिर नागरिकता कानून के तहत 2004 में नागरिकों के रजिस्टर (एनआरसी) बनाने का प्रावधान किया गया। साल 2010 में पहला राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर बनाया गया। असम जैसे राज्यों में इस पर अनेक विवाद हुए, जिसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद यूपीए और फिर भाजपा सरकार ने आधार नंबर को आगे बढ़ाया। लेकिन सत्यापन की सही व्यवस्था नहीं होने से आधार नागरिकता और निवास का सही प्रमाण नहीं माना जाता। दस्तावेजों की इन उलझनों की वजह से भारत में नागरिकों का सही रिकॉर्ड रखना एक टेढ़ी खीर बन गया है, इसलिए अवैध शरणार्थियों को भारत से वापस भेजना कानूनी तौर मुश्किल और प्रशासनिक तौर पर असंभव सा बन गया है। संसद से बनाये कानूनों को संसद या फिर सुप्रीम कोर्ट से ही रद्द किया जा सकता है। दिसंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उस वक्त सरकारी वकील ने कहा था कि अभी नियम नहीं बने हैं, इसलिए यह कानून लागू नहीं होगा। नियम जारी होने के बाद कई मुस्लिम संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर इस कानून के क्रियान्वयन पर रोक लगाने की मांग की है। इस मामले में पिछली बार तीन जजों की बेंच सुनवाई कर रही थी। लेकिन इस जटिल मामले में पांच जजों की संविधान पीठ के गठन की मांग से सुनवाई और फैसले में समय लग सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करना नेताओं का संवैधानिक अधिकार है। लेकिन राज्यों में कानून को नहीं मानने की घुड़की संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 के खिलाफ है। संसद द्वारा बनाये गये कानून और नियमों को मानने के लिए सभी राज्य सरकारें बाध्य हैं। नये कानून से भारत के नागरिकों को हासिल अनुच्छेद 14 के समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता। इसके अलावा विदेशियों को भारत में नागरिकता हासिल करने का मौलिक अधिकार नहीं है। अमेरिका और यूरोप के अनेक देशों में राष्ट्रीय सुरक्षा के अनुसार नागरिकता के नियम बनाये गये हैं। इसलिए भारत में सभी शरणार्थियों को नागरिकता देने का कानून लागू करने की मांग एकता और अखंडता के लिहाज से खतरनाक साबित हो सकती है।

नियमों की कसौटी पर कितना खरा उतरता है विपक्ष

अभिनय आकाश

हम सब भारत के संविधान की कसमें तो खूब खाते हैं या लोगों को खाते हुए सुनते हैं। पर क्या आपने संविधान देखा है? अगर कोई फोटो वगैरह में देखा भी हो तो एक चीज तो आपको पता ही होगी की अपना संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। सोने पर सुहागा ये कि पूरा संविधान हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया। हाथों से कैरीग्राफ किया गया, न कोई प्रिंटिंग हुई और न कोई टाइपिंग। इस संविधान के पहले पन्ने पर संविधान की आत्मा है। यानी संविधान की प्रस्तावना। वहीं प्रस्तावना जो %हम भारत के लोग% से शुरू होती है। लेकिन इन दिनों बीजेपी के एक सांसद के बयान के बाद संविधान में बदलाव को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। कर्नाटक से बीजेपी सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने जनसभा में कहा कि संविधान में संशोधन के लिए और कांग्रेस की ओर से इसमें जोड़ी गई अनावश्यक चीजें हटाने के लिए बीजेपी को संसद के दोनों सदनों में दो- तिहाई बहुमत की जरूरत होगी। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 पार सीटें मिलने पर राज्यसभा में बहुमत हासिल करने में मदद मिलेगी। हेगड़े के बयान पर राजनीति तेज हो गई है।

हेगड़े के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संविधान को %फिर से लिखना और नष्ट करना बीजेपी और आरएसएस का अजेंडा है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी सांसद का बयान कि उन्हें 400 सीट संविधान बदलने के लिए चाहिए, नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के छिपे मंसूबों का सार्वजनिक एलान है। कर्नाटक के सांसद की टिप्पणी को लेकर विपक्ष की ओर से सत्तारूढ़ दल पर निशाना साधने के बीच पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हमेशा संवैधानिक लोकाचार और राष्ट्रीय हित के अनुरूप काम किया है। हालांकि, आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि संविधान में इससे पहले संशोधन या बदलाव नहीं किए गए हैं। जून 1951 में संविधान में पहला संशोधन हुआ। उसके बाद ये सिलसिला लगातार

चलता रहा है। कुल संशोधनों का औसत निकाला जाए तो हर साल करीब दो संशोधन होते हैं। एक वक्त में तो इंदिरा गांधी ने एक ही संशोधन के जरिए 40

वर्ष 1971 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के मुख्य प्रतिद्वंद्वी राजनारायण ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर श्रीमती गांधी पर सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबल का प्रयोग आदि कई आरोप लगाए थे। हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम राजनारायण मामले में ऐतिहासिक फैसला देते हुए इंदिरा गांधी को चुनाव में धांधली का दोषी करार दिया और 6 वर्ष तक कोई भी पद संभालने पर प्रतिबंध लगा दिया। श्रीमती गांधी ने हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई। 24 जून, 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा। मगर श्रीमती गांधी को पद पर बने रहने का फैसला दिया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय के बाद से श्रीमती गांधी से प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने की मांग उठने लगी थी। लेकिन श्रीमती गांधी किसी भी कीमत पर त्यागपत्र देने को राजी नहीं हुईं। परिणामस्वरूप, 25 जून, 1975 को लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी के त्यागपत्र न देने तक देशभर में धरना-प्रदर्शन करने की घोषणा कर दी। अपने विरुद्ध आक्रोश को देखते हुए कुर्सी के मोह में अंधी हो चुकीं इंदिरा गांधी ने ऐसा कदम उठाया, जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। 25-26 जून, 1975 की दरम्यानी रात को इंदिरा गांधी ने देश को आपातकाल के मुंह में धकेल दिया। प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी के इशारों पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली ने संविधान की धारा-352 के अधीन देश में आपातकाल की घोषणा कर दी। आपातकाल में सबसे पहले भारतीय संविधान का 38वां संशोधन 22 जुलाई 1975 को पास हुआ। इस संशोधन के अनुसार न्यायपालिका से आपातकाल की न्यायिक समीक्षा का अधिकार छीन लिया गया। करीब दो महीने बाद इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए संविधान का 39वां संशोधन लाया गया। इलाहबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा का चुनाव रद्द कर दिया। लेकिन इस संशोधन ने कोर्ट से प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त व्यक्ति के चुनाव की जांच के अधिकार को ही छीन लिया। 40वें और 41वें संशोधन के जरिए संविधान के कई प्रावधानों को बदलने के बाद 42वां संशोधन पास किया गया।

इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ जैसे नारों के साथ एक समाजवादी और गरीब-समर्थक छवि के आधार पर जनता के बीच अपनी स्वीकृति को मजबूत करने का प्रयास किया था। लेकिन गौर करने वाली बात है कि संविधान में 42वां संशोधन, 1976 में पारित हुआ जब आपातकाल लागू था। इस दौरान संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य शब्दों को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य से बदल दिया गया। इस दौरान राष्ट्र की एकता शब्द को राष्ट्र की एकता और अखंडता में भी बदल दिया। 42वें संशोधन में कई अन्य प्रावधान थे, जिसके द्वारा इंदिरा सरकार ने सत्ता को और केंद्रीकृत करने की कोशिश की थी। हालांकि इनमें से कुछ को आपातकाल के बाद सत्ता में आई जनता सरकार ने 44वें संविधान संशोधन के जरिए रद्द कर दिया। अनुच्छेद 368(2) के तहत संसद प्रत्येक सदन में उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत से और उस सदन के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से एक विधेयक पारित करके संविधान में संशोधन कर सकती है। उसके बाद, विधेयक राष्ट्रपति को प्रस्तुत किया जाएगा जो अपनी सहमति देंगे और उसके बाद संविधान में संशोधन किया जाएगा।

छोटे देशों को शिकार बनाता चीन, नई विश्व व्यवस्था बनाने का है मंसूबा

धीरज कुमार गुप्ता

मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू लगातार ऐसे फैसले ले रहे हैं, जो चीन के साथ उनकी निकटता को ही दर्शाते हैं। छोटे पड़ोसी देशों के साथ चीन की निकटता भारत के लिए चिंताएं बढ़ाने वाली हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों चीन विश्व के ऐसे देशों की तरफ अपने पैर पसार रहा है, जो आर्थिक और सामरिक रूप से कमजोर हैं? दरअसल, चीन पूरी तरह से नई विश्व व्यवस्था बनाने का मंसूबा पाले हुए है। शी जिनपिंग की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी शासन को 2049 तक प्रमुख विश्व शक्ति बनाने की महत्वाकांक्षा है, जब वह अपने सौ वर्ष पूरे करेगी। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए चीन बेल्ट ऐंड रोड इनिशिएटिव (बीआरआई) के तहत आर्थिक एवं सामरिक रूप से कमजोर देशों को कर्ज देने की नीति का हथियार के रूप में प्रयोग कर रहा है। दूसरी ओर, चीन की आर्थिक मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का मंसूबा पाले देश उसके कर्ज के जाल में फंसकर चीन का कर्ज चुकाने में दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। चीनी सहायता प्राप्त देशों, जैसे-श्रीलंका, जांबिया, इथियोपिया, पाकिस्तान, वेनेजुएला, नेपाल, केन्या, कंबोडिया, लाओस, अफगानिस्तान और म्यांमार जैसे कई देश हैं, जो गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। अब श्रीलंका को ही ले लें, जिसने गृहयुद्ध के उपरांत आर्थिक सुधारों के लिए चीन का रुख किया, लेकिन आज उसके कर्ज-जाल में फंस गया है। श्रीलंका ने पहले 2014 और पुन: 2017 में अपने कर्ज के पुन: प्रबंधन हेतु चीन से निवेदन किया था, लेकिन उसके दोनों अनुरोध खारिज कर दिए गए थे। अंतत: जब तक श्रीलंका ने आईएमएफ से सहायता मांगने का निर्णय लिया, तब तक उसकी अर्थव्यवस्था 1948 में देश की आजादी के बाद से सबसे खराब मंदी की ओर बढ़ गई, जिससे विद्रोह भड़क गया और नतीजतन हजारों लोगों ने राष्ट्रपति को उनके घर से खदेड़ दिया था। जांबिया की भी यही स्थिति है, जिसके कुल विदेशी कर्ज का तीस फीसदी हिस्सा चीन द्वारा निर्गत किया गया है और माना जाता है कि उस पर चीनी फाइनेंसरों का लगभग छह अरब डॉलर बकाया है। इस प्रकार 2020 में, चीन के कर्ज जाल में फंसते हुए जांबिया यूरो बॉन्ड्स पर डिफॉल्ट करने वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया। चीन के कर्ज जाल में फंसे पाकिस्तान की हालत पहले से ही काफी खराब चल रही है, हालांकि उसे अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष से तीन अरब डॉलर की सहायता मिली है, जिस पर उसकी अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। नेपाल और चीन ने 2017 में बीआरआई हेतु हस्ताक्षर किए थे, लेकिन लगभग सात साल बाद एक परियोजना तक क्रियान्वित नहीं हो पाई है और इसका सबसे बड़ा कारण रहा नेपाल का पोखरा हवाई अड्डा, जो चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं था, फिर भी चीन ने इसके लिए फंड देते हुए इसे बीआरआई के अंतर्गत बताने की कोशिश की। इसी प्रकार, वेनेजुएला भी आर्थिक संकट में फंसा हुआ है, जहां सरकार पर कथित तौर पर चीन का भारी कर्ज बकाया है। तेल से समृद्ध, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर इस देश ने 2005 से चीनी कर्ज ले रखा है। चीन के साथ दिक्कत यह है कि वह जो कर्ज देता है, उसके पीछे की शर्तों को कभी सार्वजनिक नहीं करता, जैसा आईएमएफ, विश्व बैंक या पेरिस समूह करते हैं। इस वजह से चीनी कर्ज की पारदर्शिता हमेशा संदेह के दायरे में रही है। चीन चूंकि आसान शर्तों पर ऋणों को निर्गत करता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर देशों को आकर्षित करता है। कर्ज लेने वाले उन देशों को उस कर्ज के विपरीत परिणामों का एहसास तब होता है, जब उनके आर्थिक संकट बेकाबू हो जाते हैं और फिर वे इसके समाधान करने के लिए चीन से कोई रियायत प्राप्त नहीं कर पाते। उपरोक्त देशों के उदाहरणों से पता चलता है कि भले ही चीन ऋण देने की नीतियों में उदार है, लेकिन वह इसके जरिये कमजोर देशों को शिकार बनाता है।

तृप्ति डिमरी के सितारे बुलंदी पर

एनिमल मूवी में मिले चंद मिनट के रोल के बाद ही तृप्ति डिमरी के सितारे सातवें आसमान पर हैं. इस एक फिल्म के बाद ही तृप्ति डिमरी ने अपनी फीस डबल कर दी है. कार्तिक आर्यन के साथ मूवी करने के लिए वो दुगनी फीस की डिमांड कर रही हैं. इसके बावजूद वो कार्तिक आर्यन की फीस के आप पास भी नहीं पहुंच पा रही हैं. बता दें कि तृप्ति डिमरी कार्तिक आर्यन के साथ भूल भुलैया मूवी थ्री में नजर आने वाली हैं. इसके बाद भी कुछ बडे प्रोजेक्ट्स पर उनकी बातचीत जारी है. आपको बताते हैं कि भूल भुलैया 3 के लिए वो कितनी फीस ले रही हैं. एनिमल मूवी के बाद तृप्ति डिमरी के सितारे बुलंदी पर है. इस मूवी के बाद वो भूल भुलैया थ्री में नजर आने वाली हैं. खबर है कि इस फिल्म के लिए तृप्ति डिमरी डबल फीस लेने वाली हैं. एनिमल मूवी के लिए उनकी फीस 40 लाख रुपए बताई जा रही है. अब भूल भुलैया 3 के लिए वो अस्सी लाख रुपए की डिमांड कर चुकी हैं. इससे पहले भूल भुलैया 2 के लिए कियारा आडवाणी की फीस 4 से 5 करोड़ रुपए के बीच थी. अब इस फिल्म के तीसरे भाग में विद्या बालन भी नजर आने वाली हैं. इस फिल्म के बाद तृप्ति डिमरी साउथ में भी अपना जलवा दिखा सकती हैं. खबर है कि वो बाहुबली स्टार प्रभास के साथ फिल्म कर सकती हैं. मूवी का नाम स्प्रिट हो सकता है. तृप्ति डिमरी ने अपनी फीस में इजाफा तो कर लिया है लेकिन वो अब भी कार्तिक आर्यन के मुकाबले काफी पीछे हैं. भूल भुलैया थ्री में कार्तिक आर्यन तृप्ति डिमरी के को स्टार हैं. वो इस फिल्म के लिए बड़ी भारी रकम ले रहे हैं. इस फिल्म के लिए कार्तिक आर्यन की फीस 45 से 50 करोड़ रु. के बीच बताई जा रही है. जबकि तृप्ति डिमरी की फीस एक करोड़ भी नहीं पहुंच पाई है. लेकिन जिस तरह से वो कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रही हैं, उसे देखते हुए ये माना जा सकता है कि बहुत जल्द वो भी करोड़ों में फीस वसूल करेंगी.

डायरेक्टर बने सोनू

अभिनेता-समाजसेवी सोनू सूद ने अपनी आगामी फिल्म फतेह का पहला लुक साझा किया और फैंस इसके बारे में बात करना बंद नहीं कर रहे हैं। सबसे बड़ी एक्शन फिल्म में जैकलीन फर्नांडीज मुख्य भूमिका में हैं और यह नेशनल हीरो की डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म है । पोस्टर को देखकर, फैंस को आश्वासन दिया जा सकता है कि एक्टर-फिल्ममेकर एक अलग अवतार में दिखाई देंगे। सूद ने फिल्म का लेखन और निर्माण भी किया है, जो एक साइबर क्राइम थ्रिलर है।

शक्ति सागर प्रोडक्शन्स और ज़ी स्टूडियोज़ द्वारा निर्मित यह फिल्म साइबर क्राइम की जटिलताओं और चुनौतियों के इर्द-गिर्द घूमती है । फिल्म में शानदार एक्शन सीक्वेंस दिखाए जाएंगे, जो हॉलीवुड स्टंट एक्सपर्ट ली व्हिटेकर की देखरेख में किए गए हैं ।

फतेह की शूटिंग भारत, अमेरिका, रूस और पोलैंड जैसे ग्लोबल लोकेशन्स पर की गई है, जो दर्शकों को एक सिनेमाई अनुभव का वादा करता है । फिल्म के बारे में बोलते हुए, सोनू सूद ने एक बयान में कहा कि फतेह की कहानी ने उनकी रुचि जगाई । सूद ने इसे एक

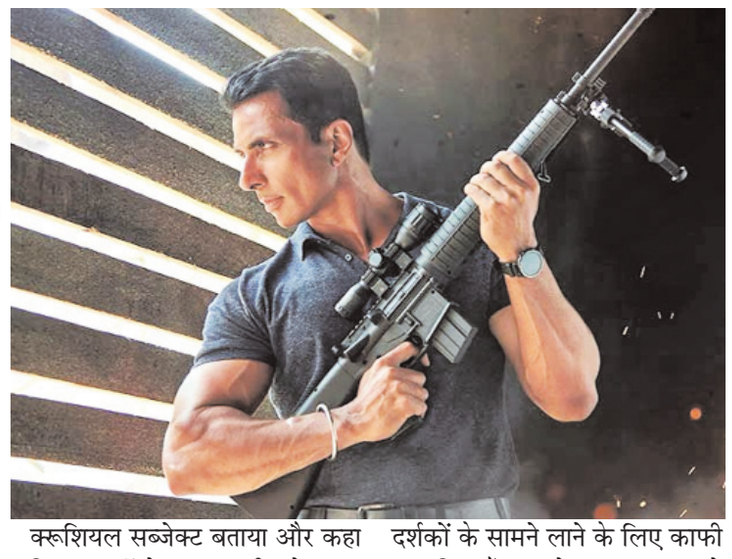

क्रूशियल सब्जेक्ट बताया और कहा कि इस कॉन्सेप्ट पर सभी को ध्यान देने की ज़रूरत है । उन्होंने यह भी बताया कि वह इस कहानी को दर्शकों के सामने लाने के लिए काफी उत्साहित हैं । फतेह इस साल बड़े पर्दे पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है।

वह अपनी काबिलियत से पहचान बना रहा

अभिनेता आर माधवन इन दिनों अपनी आगामी फिल्म शैतान को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। फिल्म रिलीज हो गई और आर माधवन के किरदार ने दर्शकों की खूब तारीफें भी बटोरी हैं, अभिनेता के लुक ने दर्शकों को पूरी तरह से आश्चर्यचकित कर दिया। आर माधवन ने हाल ही में खुलासा किया कि अपने बेटे वेदांत को वह सबसे अलग मानते हैं और भाई-भतीजावाद की बहस के बीच फिल्म इंडस्ट्री में बाकी स्टार किड्स से उनकी तुलना पर वह और उनकी पत्नी काफी निराश भी हैं। अभिनेता का मानना है कि वेदांत अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि वह सोशल मीडिया पर चल रहे मीम्स और पोस्ट को देखते हैं। हालांकि, वह ऐसे मीम्स का समर्थन नहीं करते हैं। बता दें कि माधवन के बेटे वेदांत एक तैराक हैं, जिन्होंने दुनिया भर में कई मेडल जीते हैं। उन्होंने 48वीं जूनियर नेशनल एक्वेटिक्स चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक और 3 रजत पदक जीते। पिछले साल मलेशियाई ओपन में उन्होंने भारत के लिए 5 गोल्ड मेडल जीते थे। आर माधवन ने कहा, सरिता और मैं इससे बहुत खुश नहीं हैं। एक बच्चे की तुलना दूसरे बच्चे से करने पर हमें अफसोस है। देखिए मीम्स हंसने और आनंद लेने के लिए होते है। हालांकि, मैं इनका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूं। मुझे लगता है कि यह मीम्स कई बार बहुत लोगों को काफी नुकसान पहुंचाते हैं। एक सेलिब्रिटी का बच्चा होना आसान नहीं है। वह अपने ज्यादातर दोस्तों की तुलना में बहुत अच्छा कर रहे हैं। आर माधवन के वर्कफ्रंट की बात करें, तो अभिनेता के पास इस साल चार फिल्में पाइपलाइन में हैं। आर माधवन फिल्म %शैतान% के अलावा फिल्म %टेस्ट% में काम करेंगे। इस फिल्म में उनके साथ साउथ अभिनेत्री नयनतारा नजर आएंगी। इसके साथ ही आर माधवन की तमिल फिल्म %अधिरष्टसाली% और %जीडी नायडू बायोपिक% भी पाइपलाइन में हैं।

सिद्धार्थ मल्होत्रा के कूल स्टाइल एक्शन और अलग तरह की कहानी के कारण क्रैश होने से बची योद्धा

योद्धा एक बहादुर अधिकारी की कहानी है । साल है 2001 है, अरुण कात्याल (सिद्धार्थ मल्होत्रा) योद्धा टास्क फोर्स का हिस्सा हैं । वह अपनी पत्नी प्रियंवदा (राशि खन्ना), रक्षा मंत्रालय में सचिव और अपनी बीमार मां (फरीदा पटेल) के साथ दिल्ली में रहते हैं । अरुण के पिता सुरेंद्र कात्याल (रोनित रॉय) नहीं रहे । मैदान पर लड़ते हुए उनकी मृत्यु हो जाती है । उन्होंने योद्धा टास्क फोर्स की शुरुआत की और अरुण अपने पिता के नक्शेकदम पर चलना चाहते हैं । हालाँकि, वह आदेशों का पालन न करने के लिए बदनाम है । उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उनके सभी ऑपरेशन सफल रहे हैं । एक दिन, वह एक परमाणु वैज्ञानिक, अनुज नायर (एसएम जहीर) को सुरक्षा प्रदान करते हुए एक उड़ान पर जाते है । फ्लाइट हाईजैक हो जाती है और उसे जबरन अमृतसर हवाई अड्डे पर उतारा जाता है । योद्धा सेनानी हवाई अड्डे पर पहुंचते हैं और अरुण को एक संकेत देते हैं, जो दर्शाता है कि वह अपनी किस्मत आजमा सकता है और हाईजैकर को हरा सकता है। वह इसके लिए जाता है, उम्मीद करता है कि योद्धा टीम जल्द ही हवाई जहाज तक पहुंच जाएगी और अपराधियों को पकड़ लेगी। नौकरशाही बाधाओं के कारण ऐसा कभी नहीं होता। अपहर्ताओं से लड़ते हुए अरुण को विमान से बाहर फेंक दिया जाता है । अनुज नायर मारा गया । एक जांच आयोग ने अरुण को दोषी पाया और यह भी सिफारिश की कि योद्धा टास्क फोर्स को भंग कर दिया जाना चाहिए । इसके परिणामस्वरूप अरुण और प्रियंवदा के बीच लड़ाई भी होती है । दोनों अलग होने का फैसला कर लेते हैं । अरुण टूट जाता है । पांच साल बाद, अरुण को खुद को बचाने का मौका मिलता है । आगे क्या होता है इसके लिए पूरी फ़िल्म देखनी होगी ।

सागर अम्ब्रे की कहानी में एक सामूहिक मनोरंजन के सभी एलिमनेट्स मौजूद हैं । सागर अंब्रे की पटकथा अनोखी है, क्योंकि यह ट्रेडिशनल हाईजैक फिल्मों के टेम्पलेट को फ़ोलो नहीं करती है। हालाँकि, कई बार लेखन भ्रमित करने वाला हो जाता है । सागर अम्ब्रे के डॉयलॉग्स यथार्थवादी हैं और उनमें से कुछ हीरो स्टाइल के हैं ।

सागर अम्ब्रे और पुष्कर ओझा का निर्देशन काफी अच्छा है, यह देखते हुए भी कि यह उनकी पहली निर्देशित फिल्म है । निर्देशक जोड़ी मुख्यधारा की एक्शन फिल्मों के व्याकरण को जानती है और इसका प्रभावी ढंग से उपयोग करती है । वे दर्शकों को उनके पैसे वसूलने के लिए एक्शन और उड़ान के दौरान होने वाली घटनाओं पर अधिक ध्यान केंद्रित रखने की पूरी कोशिश करते हैं। कुछ दृश्य जो उभरकर सामने आते हैं, वे हैं- अरुण की एंट्री, अरुण वैज्ञानिक को बचाने की कोशिश करना और एयर भारत की उड़ान में होने वाला पागलपन । क्लाइमेक्स की लड़ाई दिलचस्प है ।

वहीं कमियों की बात करें तो, यह बहुत अधिक तकनीकी है इसलिए फिल्म को नुकसान उठाना पड़ता है । फिल्म देखने वालों का एक बड़ा वर्ग अरुण और पायलट के बीच फ्लाइट को उतारने में आने वाली चुनौतियों को समझने में भ्रमित हो जाएगा । इसके अलावा, इंटरमिशन प्वाइंट दर्शकों को अपना सिर खुजलाने पर मजबूर कर देगा और सोचेंगे कि वास्तव में क्या हो रहा है । शुक्र है, सेकेंड हाफ़ में कहानी स्पष्ट हो जाती है लेकिन फिर भी, कुछ पहलू दर्शकों के दिमाग से ऊपर निकल जाएँगे ।

सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत अच्छा अभिनय किया है और वह इस रोल के लिए परफ़ेक्ट लगते हैं । एक्शन करते वक्त वह कूल दिख रहे हैं और क्लाइमेक्स में उनका स्वागत सीटियों और तालियों से होगा । राशि खन्ना शानदार हैं और ऐसे मजबूत किरदार के लिए बिल्कुल सही हैं । दिशा पटानी (लैला) के पास शुरू में करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है लेकिन वह सेकेंड हाफ़ में छा जाती हैं । कृतिका भारद्वाज (तान्या शर्मा) फिल्म का सरप्राइज़ है; वह बहुत अच्छा करती है । फिल्म में सनी हिंदुजा (रफीक) को काफी बाद में प्रमुखता मिलती है। फिर भी, वह एक छाप छोड़ जाते है। तनुज विरवानी (समीर खान) सक्षम समर्थन देते हैं । चितरंजन त्रिपाठी (एस एन ढींगरा) सभ्य हैं । फरीदा पटेल के पास एक भी संवाद नहीं है । रोनित रॉय, हमेशा की तरह, एक छोटी भूमिका में जँचते हैं। एस एम ज़हीर, मिखाइल यावलकर (अहमद खालिद) और संजय गुरबक्सानी (भारतीय राष्ट्र प्रमुख) निष्पक्ष हैं।

संगीत औसत है। जिंदगी तेरे नाम की, तेरे संग इश्क हुआ और किस्मत भावपूर्ण हैं लेकिन चार्टबस्टर किस्म के नहीं हैं । तिरंगा%कथा में अच्छी तरह बुना गया है। जॉन स्टीवर्ट एडुरी के बैकग्राउंड स्कोर में सिनेमाई अहसास है । जिष्णु भट्टाचार्जी की सिनेमैटोग्राफी साफ-सुथरी है। सुब्रत चक्रवर्ती और अमित रे का प्रोडक्शन डिज़ाइन और थिया टेकचंदनी की वेशभूषा यथार्थवादी लेकिन आकर्षक हैं।

क्रेग मैक्रै और सुनील रोड्रिग्स का एक्शन काफी अच्छा है और बिल्कुल भी परेशान करने वाला नहीं है। कुल मिलाकर, योद्धा सामान्य हाईजैक फिल्म नहीं है और इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा का बेहतरीन अभिनय है । हालाँकि, क्योंकि यह काफी तकनीकी रूप से भ्रमित करने वाली है इसे बॉक्स ऑफिस पर संघर्ष करना पड़ेगा ।

प्रियंका का दिखा स्टाइलिश लुक

रंगों का त्योहार होली करीब आ रहा है। ऐसे में बॉलीवुड में भी इस त्योहार की धूम देखने को मिल रही है। हर साल की तरह इस बार भी स्टार्स के घर होली पार्टी होस्ट की जाएंगी। वहीं अब होली से पहले बिजनेसमैन मुकेश अंबानी की बेटी एक पार्टी की मेजबानी की, जिसमें बॉलीवुड के कई स्टार्स ने शिरकत की। इस शानदार पार्टी में आयुष्मान खुराना, शिल्पा शेट्टी, ओरी, अथिया शेट्टी, माधुरी दीक्षित और कई सेलेब्स ने शिरकत की हालांकि सबकी नजर सिर्फ देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पर टिकी। प्रियंका ने प्री-होली पार्टी में शानदार ड्रेस में सुंदरता बिखेरी। पार्टी में प्रियंका चोपड़ा ने हाई स्लिट साड़ी में अपना स्टाइलिश अंदाज दिखाया। हाई स्लिट साड़ी के साथ प्रियंका चोपड़ा ने बड़े-बड़े स्टोन्स वाला नेकलेस कैरी किया था।इस तस्वीर में देख सकते हैं कि प्रियंका के नेकलेस में रेड और ब्लू कलर के स्टोन्स हैं। इस हार की कीमत 8 करोड़ 33 लाख 80 हजार बताई जा रही है। ईशा अंबानी और बुल्गारी रोमन होली पार्टी के लिए प्रियंका ने मोव ब्लश मेकअप के साथ लाइट पिंक शेड की लिपस्टिक कैरी की थी। साथ ही एक्ट्रेस ने अपने बालों को बीच से पार्टीशन करके ओपन लुक में छोड़ा था। फैंस प्रियंका की इन तस्वीरों को काफी पसंद कर रहे हैं।

एक स्त्री के संघर्ष की गाथा हैं 'भूख मया के'

श्याम सिनेमा सहित 18 सेंटर्स में प्रदर्शित हुई छत्तीसगढ़ी फ़िल्म भूख मया के को दर्शको की ओर से ओर से भरपूर मया मिला छत्तीसगढ़ी फिल्म भूख मया के के प्रीमियर शो के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए अभिनेत्री गरिमा शर्मा ने कहा कि इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिलना चाहिए क्योंकि एक स्त्री के संघर्ष की गाथा है। उन्होंने फिल्म में अपनी भूमिका महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि एक गूंगी लड़की का किरदार निभाना बहुत ही कठिन था, पर मैंने इसे दिल से निभाया है। छत्तीसगढ़ी और राजस्थान बोली में कोई फर्क नहीं है, जहां की जैसी बोलचाल होती है वहां के बोलचाल में ढलना कलाकारों को बखूबी आता है।

अगर फिल्म की बात करें तो मध्यांतर तक यह समझ नहीं आता हैं पर मध्यांतर के बाद पूरी कहानी समझने में दर्शकों को समय नहीं लगेगा। संयुक्त परिवार के इर्द गिर्द घूमती कहानी दर्शको को बहुत पसंद आई फ़िल्म के सभी गाने भी कर्ण प्रिय बनाये गए है खासकर दिलेश साहू नायिका गरिमा शर्मा ने अपने किरदार में न्याय किया खासकर महिलाओं को बहुत पसंद आया है गरिमा का अभिनय दिलेश ने अभिनय के साथ डांस में दर्शको का दिल जीता है रियाज़ खान एवं नेहा शुक्ला ने बेहतरीन एक्टिंग की है दिलेश एवं रियाज़ की माता की भूमिका में उपासना ने चार चांद लगा दिये है फिर भी एक बार परिवारिक ड्रामा कॉमेडी फिल्म देखने लायक जो दर्शको की पसंद बानी हुई है फ़िल्म के वितरण का सम्पूर्ण कार्य भर माँ फिल्मस रायपुर तरुण सोनी ने संभाला है।

स्टाइलिश लुक में न्यूयॉर्क की सड़कों पर स्पॉट हुईं गिगी हदीद

अमेरिकन फैशन मॉडल गिगी हदीद अपने फैशन स्टेंटमेंट को लेकर हमेशा चर्चा में रहती है। मॉडल की बोल्ड तस्वीरें सोशल मीडिया पर तहलका मचा देती हैं। हाल ही में गिगी को न्यूयॉर्क की सड़कों पर स्पॉट किया गया। इस दौरान हसीना ऑल ब्लैक लुक में दिखीं। लुक की बात करें तो गिगी ब्लैक टॉप, स्किनफिट जैगिंग और मैचिंग कोट में स्टाइलिश दिख रही हैं। मिनिमल मेकअप, ब्लैक शेड्स हसीना के लुक परफेक्ट बना रही हैं। इसके साथ ही गिगी का न्यू हेयरकट यानि शॉर्ट हेयर्स उनके लुक को चार-चांद लगा रहे हैं। गिगी न्यूयॉर्क की सड़क पर स्टाइलिश अंदाज में पोज दे रही हैं।

राजपूत की फिल्म 'ससुराल का गुलाम' का फर्स्ट लुक रिलीज

भोजपुरी सिनेमा के जानेमाने अभिनेता विक्रांत सिंह राजपूत की आने वाली फिल्म 'ससुराल का गुलाम' का फर्स्ट लुक रिलीज हो गया है। फिल्म ससुराल का गुलाम में विक्रांत सिंह राजपूत के साथ यामिनी सिंह मुख्य में हैं। इस फिल्म के निर्माता संदीप सिंह और अरविंद अग्रवाल हैं।निर्देशक इश्तियाक शेख बंटी हैं। कथा - पटकथा और संवाद अरविंद तिवारी का है। विक्रांत सिंह राजपूत ने फिल्म 'ससुराल का गुलाम' को लेकर कहा कि यह फिल्म भी बेहद ख़ास होने वाली है। यह फिल्म आधी आबादी को खूब पसंद आएगी। मेरा किरदार इस फिल्म में अनोखा है। उम्मीद करता हूं कि यह सबों को पसंद आये।फिल्म के गाने भी बेहद खूबसूरत हैं। फिल्म में यामिनी सिंह के साथ मेरी केमेस्ट्री दर्शकों के दिलों को छूने वाली है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

सरकार ने जेकेएलएफ पर प्रतिबंध 5 साल के लिए बढ़ाया

नईदिल्ली। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एक्शन लिया है। मोदी सरकार ने 16 मार्च को यासीन मलिक के जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) को अगले पांच साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने 'जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट' (यासीन मलिक धड़े) को और पांच वर्ष के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित किया है। अमित शाह ने कहा कि जेकेएलएफ (यासीन मलिक धड़ा) जम्मू कश्मीर में आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों में लिप्त है। अगर कोई देश की सुरक्षा, संप्रभुत्ता और अखंडता को चुनौती देते हुए पाया गया तो उसे कठोर कानूनी परिणाम भुगतने होंगे। मोदी सरकार ने 'जम्मू कश्मीर पीपुल्स फ्रीडम लीग' को भी अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित किया।

अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से मिली राहत

नई दिल्ली। अरविंद केजरीवाल को ईडी की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दे दी है। 15,000 रुपये के जमानत बांड और 1 लाख रुपये की जमानत राशि जमा करने पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट राहत मिली। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद वे पूछताछ के लिए दिव्या मल्होत्रा के सामने पेश हुए। दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट एसीएमएम ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके और 1 लाख रुपए की जमानत राशि पर बेल दी। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ईडी की दो शिकायतों के आधार पर अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन के बाद सीएम अदालत में पेश हुए। आम आदमी पार्टी के लीगल हेड संजीव नासियार ने कहा, अदालत ने मुख्यमंत्री(अरविंद केजरीवाल) को तलब किया था।

मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल भाजपा में शामिल

नईदिल्ली। 80 और 90 के दशक में अपने हिट गानों और भक्ति संगीत के लिए मशहूर गायिका अनुराधा पौडवाल शनिवार को नई दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गईं। पौडवाल ने कहा कि वह ऐसी सरकार में शामिल होकर खुश हैं जिसका सनातन धर्म से गहरा संबंध है। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अनुराधा पौडवाल ने कहा कि मुझे खुशी है कि मैं उस सरकार में शामिल हो रही हूं जिसका सनातन (धर्म) से गहरा संबंध है। यह मेरा सौभाग्य है कि मैं आज भाजपा में शामिल हो रही हूं। पौडवाल ने कई भाषाओं में हजारों गाने और सैकड़ों भजन गाए हैं। कर्नाटक के कारवार में जन्मीं पौडवाल ने महज 19 साल की उम्र में हिट फिल्म अभिमान के ओमकारम बिंदु संयुक्तम से अपने गायन की शुरुआत की। इस गाने को एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया था, जिनके साथ उन्होंने कई बार काम किया।

वरूण का टिकट कटा तो मेनका पीलीभीत से फिर लड़ सकती हैं

नईदिल्ली। सुलतानपुर से गांधी परिवार का काफी आत्मीयता का संबंध रहा है। यहां से गांधी परिवार या उसके वफादार चुनाव भी जीतते रहे हैं, इस समय सुलतानपुर से से बीजेपी नेता मेनका गांधी सांसद हैं, लेकिन मेनका को लेकर बीजेपी आलाकमान ने अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। अयोध्या से सटी सुलतानपुर सीट भी सत्तादल और विपक्ष के लिए खास मायने रखती है। यही वजह है कि दावेदारों की खूब जांच-परख करने के बाद ही घोषणा की जाती है। इस बड़ी सीट पर लोकसभा चुनाव में बड़ा दांव आजमाने की जुगत में भाजपा व विपक्षी दल दोनों ही लगे हुए हैं। इसी कारण से अब तक जहां भाजपा वर्तमान सांसद मेनका गांधी को यहां से चुनाव लड़ाने की घोषणा नहीं कर सकी, वहीं, इंडी गठबंधन और बसपा भी मौके की तलाश में हैं। इस बीच खबर यह भी है कि मेनका गांधी को यहां के बजाय पीलीभीत से एक बार पार्टी फिर मौका देना चाहती है। यदि ऐसा होता है तो सुलतानपुर से बीजेपी पिछड़ी जाति, वह भी कुर्मी बिरादरी का उम्मीदवार उतार सकती है।

राज ठाकरे की एमएनएस हो सकती है भाजपा में शामिल

मुंबई। सूत्रों ने शनिवार (16 मार्च) को कहा कि राज ठाकरे के नेतृत्व वाली मनसे लोकसभा चुनाव से पहले जल्द ही भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो सकती है। गठबंधन पर चर्चा अंतिम चरण में है. एमएनएस प्रमुख ने पार्टी के लिए दक्षिण मुंबई सीट की मांग की है. सूत्रों ने कहा कि कम से कम एक सीट मिलने के बाद ही उनकी पार्टी एनडीए में शामिल होगी। राज ठाकरे एनडीए में शामिल हो सकते हैं। राज ठाकरे के एनडीए में शामिल होने की चर्चा अंतिम चरण में है। एमएनएस अध्यक्ष दक्षिण मुंबई सीट पर एमएनएस उम्मीदवार देने की मांग कर रहे हैं। इस सीट पर बीजेपी से राहुल नार्वेकर के नाम पर पहले से ही चर्चा चल रही है। राज ठाकरे की मांग पर बीजेपी की ओर से अभी फैसला नहीं हुआ है। सूत्रों ने कहा, राज ठाकरे कम से कम एक सीट हासिल करने के बाद ही एनडीए में शामिल होंगे। इससे पहले, उद्धव ठाकरे ने अरविंद सावंत को दक्षिण मुंबई से पार्टी का उम्मीदवार घोषित किया था।

नगरकुर्नूल में जनसभा में बोले प्रधानमंत्री- देश ने घोषणा कर दी है अबकी बार 400 पार

दशकों तक कांग्रेस ने देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया: मोदी

हैदराबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को दक्षिण के दो राज्यों के दौरे पर थे। लोकसभा चुनावों में 370 सीटें जीतने के लक्ष्य के लिए पीएम मोदी लगातार रैलियां कर रहे हैं। पीएम मोदी तेलंगाना नगरकुर्नूल में वह एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि शनिवार को देश में 2024 के चुनाव का बिगुल बज गया है। लेकिन चुनाव के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का एलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है- अबकी बार 400 पार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, तेलंगाना में विधानसभा के चुनाव के दौरान मैं यहां आया था तब मैंने देखा था कि जनता के दिल और दिमाग में बीआरएस के खिलाफ इतना गुस्सा था और उसका नतीजा भी हमने देखा कि उसका क्या हाल हुआ है... अब तेलंगाना के लोगों ने मोदी को फिर से वापस लाने का फैसला सुना दिया है।

पीएम मोदी ने कहा, तेलंगाना को हमारे देश में गेटवे ऑफ साउथ कहा जाता है। यह एनडीए और मोदी की प्राथमिकता रहा है, इन 10 वर्षों में हमने देखा कि कैसे तेलंगाना चक्की के दो हिस्सों में पिसता रहा है जिसमें एक हिस्सा कांग्रेस का और दूसरा हिस्सा बीआरएस का था। कांग्रेस और बीआरएस ने मिलकर तेलंगाना के विकास के हर सपने को चकनाचूर कर दिया है। अब तो मुश्किल यह है कि यहां कांग्रेस के पंजे का कब्जा हो गया है। पहले बीआरएस की महा लूट और कांग्रेस की बुरी नजर... कांग्रेस के लिए पूरा राज्य तबाह करने के लिए पांच वर्ष भी बहुत हैं।

उन्होंने कहा, कांग्रेस ने दशकों तक देश में गरीबी हटाओ का नारा दिया। लेकिन, गरीब के जीवन में कोई बदलाव आया क्या? कांग्रेस ने एससी, एसटी, ओबीसी को वोटबैंक के तौर पर इस्तेमाल किया। लेकिन, समाज के हालात सुधरे क्या? बदलाव तब आया, जब देश ने मोदी को पूर्ण बहुमत का आशीर्वाद दिया। क्योंकि, बदलाव की एक ही गारंटी है। मोदी की गारंटी।

उन्होंने आगे कहा, बीआरएस भी कांग्रेस के ही नक्शेकदम पर चलने वाली पार्टी है। केसीआर तो कहते हैं कि भारत को नए संविधान की जरूरत है। क्या ये बाबा साहब डॉ. अंबेडकर को अपमानित करने का कृत्य नहीं है? केसीआर ने दलित बंधु योजना से दलितों को धोखा दिया।

मुझे विश्वास है आशीर्वाद मिलता रहेगा प्रधानमंत्री ने शेयर किया भावुक पत्र

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा से पूर्व पीएम मोदी ने 140 करोड़ देशवासियों के नाम पत्र शेयर किया है। इस पत्र में उन्होंने देशवासियों का ध्यान मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल के दौरान लिए गए ऐतिहासिक फैसलों की ओर आकर्षित किया है। पीएम ने लिखा कि आपका और हमारा साथ अब एक दशक पूरा करने जा रहा है। मेरे 140 करोड़ परिवारजनों के साथ विश्वास, सहयोग और समर्थन से जुड़ा यह मजबूत रिश्ता मेरे लिए कितना विशेष है, इसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है।

मेरे परिवारजनों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव ही बीते 10 वर्षों में हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी है। अपनी हर नीति, हर निर्णय के जरिए गरीबों, किसानों, युवाओं और महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए कृतसंकल्पित सरकार ने जो ईमानदार प्रयास किए हैं, उनके सार्थक परिणाम हमारे सामने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए पक्के मकान, सभी के लिए बिजली, पानी, गैस की समुचित व्यवस्था, आयुष्मान भारत योजना के जरिए इलाज की व्यवस्था, किसान भाई-बहनों को आर्थिक मदद, मातृ वंदना योजना के जरिए माताओं-बहनों को सहायता जैसे अनेक प्रयास सिर्फ और सिर्फ इसलिए फलीभूत हो पाए हैं, क्योंकि आपका भरोसा, आपका विश्वास मेरे साथ था। विकास और विरासत को साथ लेकर आगे बढ़ते भारत ने बीते एक दशक में जहां बुनियादी ढांचों का अभूतपूर्व निर्माण देखा, तो वहीं हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय धरोहरों के पुनरुत्थान का साक्षी बनने का गौरव भी प्राप्त हुआ। अपनी समृद्ध संस्कृति और परंपरा को सहेजकर आगे बढ़ते देश पर आज हर देशवासी को गर्व है। यह आपका विश्वास और समर्थन ही था कि जीएसटी लागू करना, धारा 370 समाप्त करना, तीन तलाक पर नया कानून, संसद में महिलाओं के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नये संसद भवन का निर्माण, आतंकवाद और नक्सलवाद पर कठोर प्रहार जैसे अनेक ऐतिहासिक और बड़े फैसले लेने से हम चूके नहीं। लोकतंत्र की खूबसूरती जनभागीदारी और जनसहयोग में है।

देशहित के लिए बड़े फैसले लेने, बड़ी योजनाएं बनाने और उन्हें सुचारू रूप से लागू कर पाने की शक्ति और ऊर्जा मुझे आपके विश्वास और सहयोग से ही प्राप्त होती रही है। विकसित भारत के निर्माण के जिस संकल्प के साथ देश आगे बढ़ रहा है, उसकी पूर्ति में मुझे आपके विचारों, सुझावों, साथ और सहयोग की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद और समर्थन हमें निरंतर मिलता रहेगा। राष्ट्रनिर्माण के लिए हमारे प्रयास बिना थके, बिना रुके अनवरत जारी रहेंगे, यह मोदी की गारंटी है।

मोदी ने शुरू किया मेरा भारत, मेरा परिवार कैंपेन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा भारत, मेरा परिवार कैंपेन की शुरुआत की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें कैंपेन का थीम गीत जारी किया गया है। आज ही चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का एलान करने वाला है। इस कैंपेन के तहत साझा किए गए वीडियो में मोदी सरकार की किसान सम्मान निधि योजना, हर घर नल योजना, उज्जवला योजना और पीएम आवास योजना जैसी योजनाओं को दिखाया गया है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी मेरा भारत, मेरा परिवार कैंपेन के थीम सॉन्ग को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया है। साथ ही केंद्रीय सूचना मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस थीम सॉन्ग को सोशल मीडिया पर री-पोस्ट किया है।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष का केंद्र सरकार पर हमला

चुनावी बॉन्ड योजना एक जबरन वसूली रैकेट: राहुल गांधी

मुंबई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को एक बार फिर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला किया। उन्होंने चुनावी बॉन्ड योजना को सरकारों को गिराने और राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जबरन वसूली रैकेट बताया। बता दें, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी महाराष्ट्र के थाने में जंभाली नाका के पास लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया, चुनावी बॉन्ड योजना अंतरराष्ट्रीय स्तर का जबरन वसूली रैकेट है। जो लोग इसका विरोध करते हैं, प्रवर्तन निदेशालय, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और आयकर विभाग उनके पीछे पड़ जाते हैं। चुनावी बॉन्ड योजना का सरकारों को गिराने और राजनीतिक दलों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजित पवार के नेतृत्व में हुए बगावत से दो पार्टियों के विभाजित होने पर सवाल उठाते हुए राहुल ने कहा, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) के विधायक मुफ्त में चले गए? कांग्रेस नेता ने कहा कि पिछड़े समुदायों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों और सामान्य श्रेणी के गरीबों की आबादी 80 प्रतिशत से अधिक है, लेकिन सरकारी और निजी क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर उनका प्रतिनिधित्व बेहद कम है। उन्होंने दावा किया कि भारत में कोविड-19 से 50 लाख लोगों की मौत हुई।

राहुल गांधी ने कहा, जब लोग कोरोना वायरस से मर रहे थे, टीका बनाने वाली कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनावी बॉन्ड के रूप में पैसा दिया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अयोध्या में राम मंदिर की भूमि पूजन समारोह में केवल फिल्मी सितारे और शीर्ष उद्योगपति मेहमान के तौर पर शामिल किए गए। वहां कोई गरीब मौजूद नहीं था। यहां तक कि भारत की

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी कार्यक्रम में आने की अनुमति नहीं दी गई क्योंकि वह आदिवासी हैं। राहुल गांधी की यात्रा के ठाणे में प्रवेश के दौरान उनके साथ शरदचंद्र पवार वाली एनसीपी के विधायक जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना (यूबीटी) नेता केदार दिघे भी मौजूद थे। जिले के भिवंडी में समाजवादी पार्टी के विधायक रईस शेख ने उनका स्वागत किया। वहीं कांग्रेस नेता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड्स के नाम पर 'हफ्ता वसूली सरकार' ने दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया है। कंपनियों से एक्सटोर्शन का यह मॉडल खुद नरेंद्र मोदी का तैयार किया हुआ था। उन्होंने कहा कि इस आपराधिक खेल के नियम स्पष्ट थे। पहला एक तरफ कॉन्ट्रैक्ट दिया, दूसरी तरफ से काट लिया। दूसरा- एक तरफ से रेड की, दूसरी तरफ चंदा लिया।

उन्होंने आगे कहा कि ईडी, आईटी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां नरेंद्र मोदी की 'वसूली एजेंट' बन कर काम कर रही हैं। जो कभी देश के संस्थान हुआ करते थे वो अब भाजपा के हथियार के रूप में काम कर रहे हैं। भारतीय मीडिया इस स्थिति में नहीं है कि वह चुनावी बॉन्ड की सच्चाई जनता को बता सके, इसलिए आपको खुद ही भाजपा का असली चेहरा पहचानना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकारी तंत्र को पूरी तरह संगठित भ्रष्टाचार में झोंक देने वाले नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत से बाहर हो सकता है आईपीएल का दूसरा चरण

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) लोकसभा चुनाव को देखते हुए आईपीएल 2024 के दूसरे चरण का आयोजन भारत से बाहर करने पर विचार कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, बीसीसीआई के अधिकारी यूएई में हैं और आईपीएल का दूसरा चरण गल्फ देश में कराने की संभावना तलाश रहे हैं। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख आईपीएल के दूसरे चरण से टकरा सकती हैं। चुनाव घोषित होने के बाद ही बीसीसीआई आईपीएल का अगला चरण देश के बाहर कराने पर कोई अंतिम निर्णय ले सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों से उनके पासपोर्ट जमा करने के लिए भी कह दिया है। इससे पहले 2014 में भी आईपीएल का पहला चरण लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूएई में आयोजित कराया जा चुका है। हालांकि, 2019 में लोकसभा चुनाव होने के बावजूद आईपीएल का पूरा सीजन भारत में ही हुआ था। सिर्फ 2009 में ही आईपीएल पूरी तरह से विदेश में (दक्षिण अफ्रीका) खेला गया था। यह देखते हुए कि टी20 विश्व कप आईपीएल के खत्म होने के कुछ दिनों के बाद ही शुरू हो जाएगा, फाइनल 26 मई को होने की संभावना है। भारत विश्व कप में अपना पहला मैच पांच जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगा, जबकि आईसीसी टूर्नामेंट की शुरुआत एक जून को अमेरिका और कनाडा के बीच मैच से होगी। लोकसभा चुनाव की घोषणा नहीं होने के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल 2024 का पूरा कार्यक्रम घोषित नहीं किया था। बोर्ड ने इस लोकप्रिय टूर्नामेंट के 17वें सीजन के पहले चरण का कार्यक्रम घोषित किया था जिसमें 21 मैच शामिल थे। आईपीएल के पहले चरण का 22 मार्च को चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) और रायल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) के बीच होने वाले मैच से शुरू होगा।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

असम में 13,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश आया

गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व सरमा ने कहा है कि राज्य ने पिछले 14 महीनों में 13,364 करोड़ रुपये का निवेश हासिल किया है, जिससे 17,000 से ज्यादा लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। यह निवेश असम की औद्योगिक और निवेश नीति (आईआईपीए), 2019 के तहत राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 21 प्रस्तावों के माध्यम से प्रतिबद्ध किया गया है। उन्होंने शुक्रवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, आईआईपीए को 2023 में 100 करोड़ रुपये और उससे अधिक के ऐसे निवेश को आकर्षित करने के लिए संशोधित किया गया था, जहां 200 या अधिक स्थायी रोजगार के अवसर तैयार होने थे। उन्होंने कहा कि इनमें से जहां 14 प्रस्तावों के लिए एमओयू पर पहले हस्ताक्षर किए गए थे, वहीं सात समझौतों पर शुक्रवार को हस्ताक्षर किए गए।

सेबी ने कारोबार को आसान बनाने के उपायों को मंजूरी दी

नईदिल्ली। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने शुक्रवार को बाजार सहभागियों के लिए व्यापार को और सुगम बनाने के वास्ते कई उपायों को मंजूरी दे दी। इन उपायों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) और प्रारंभिक शेयर बिक्री के माध्यम से धन जुटाने की चाहत रखने वाली इकाइयों को छूट प्रदान करना शामिल है। सेबी बोर्ड ने शुक्रवार को अपनी बैठक के दौरान प्रस्तावों को मंजूरी दी। सेबी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इक्विटी शेयर के सार्वजनिक/राइट्स इश्यू में एक प्रतिशत 'सुरक्षा जमा' की आवश्यकता को खत्म करने और अप्रत्याशित घटना के कारण ऑफर समापन तिथि के विस्तार को लचीलापन बनाने का निर्णय लिया गया है। ये उपाय आईपीओ और धन जुटाने के लिए आने वाली कंपनियों के वास्ते व्यापार करना सुगम बनाने के प्रयासों का हिस्सा हैं।

अमेरिकी अदालत ने फ्रीज किए बायजू के 533 मिलियन डॉलर

नईदिल्ली। एडटेक कंपनी बायजू की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही हैं। एक बार फिर से कंपनी को बड़ा झटका लगा है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी कोर्ट ने गुरुवार को कंपनी के 533 मिलियन डॉलर के फंड को फ्रीज करने का फैसला सुनाया है। कोर्ट के मुताबिक कंपनी को इस रकम को ट्रांसफर करने या इस्तेमाल करने से रोक दिया है। ये रकम पहले हेड फंड के पास थी, लेकिन अब इसे किसी अज्ञात ऑफशोर ट्रस्ट में ले जाया गया है। कोर्ट के इस फैसले को कंपनी के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे कर्जदाताओं की जीत माना जा रहा है। इसी के साथ अदालत के जज जॉन टी. डोर्सी ने हेज फंड कैमशाफ्ट कैपिटल के फाउंडर विलियम मॉर्टन को गिरफ्तार करने का आदेश भी दिया है। बताया गया है कि मॉर्टन बार-बार अदालत में पेश होने और रकम के ट्रांसफर के बारे में जानकारी देने से इनकार कर रहे थे।

अगले हफ्ते आ रहा है चाथा फूड कंपनी का आईपीओ

नईदिल्ली। अगले हफ्ते यानी 19 मार्च को प्रोसेस्ड फूड बनाने वाली कंपनी चाथा फूड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुलने जा रहा है। कंपनी का ये 34 करोड़ का आईपीओ बोली लगाने के लिए 21 मार्च तक खुला रहेगा। इस आईपीओ के तहत कंपनी के 59.62 लाख नए शेयर जारी किए जाएंगे। 21 मार्च को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद होने के बाद इस कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग 27 मार्च 2024 को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर हो सकती है। प्राइस बैंड की बात करें को इसके लिए 53 से 56 रुपये प्रति शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। लॉट साइज 2000 शेयरों का है। इश्यू के रिजर्व हिस्से की बात करें को इश्यू का 50 प्रतिशत हिस्सा क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए, 35 प्रतिशत हिस्सा रिटेल इनवेस्टर्स के लिए और 15 प्रतिशत हिस्सा नॉन इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स के लिए रिजर्व रखा गया है।

विदेशी व्यापार समझौते में सतर्कता जरूरी

केसी त्यागी/बिशन नेहवाल

आखिर 16 साल की लंबी बातचीत के बाद 10 मार्च, 2024 को भारत ने यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (इएफटीए) के साथ एक ऐतिहासिक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर कर दिये। इस संघ में स्विट्जरलैंड, आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे शामिल हैं।

इस समझौते में कुल 14 अध्याय हैं, जिनमें वस्तुओं से संबंधित बाजार पहुंच, उद्भव के नियम, व्यापार सुगमीकरण, व्यापार उपचार, स्वच्छता एवं पादप स्वच्छता उपाय, व्यापार से संबंधित तकनीकी बाधा, निवेश संवर्धन, सेवाओं पर बाजार पहुंच, बौद्धिक संपदा अधिकार, व्यापार एवं सतत विकास तथा अन्य प्रावधान शामिल हैं। इसमें 100 अरब डॉलर के निवेश और 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार की प्रतिबद्धता है। प्रभावी होने के दो साल बाद इसकी समीक्षा का प्रावधान है। पहली समीक्षा के बाद दोनों पक्ष हर दो साल में समीक्षा करेंगे।

यह व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौता (टीइपीए) दोनों पक्षों के लिए महत्वपूर्ण आर्थिक लाभ का वादा करता है, लेकिन करीब से देखने पर भारत के लिए संभावित फायदे और चुनौतियों की एक जटिल क्रिया का पता चलता है। समझौते में आर्थिक सहयोग के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनमें शुल्कों में कमी मुख्य है। भारत ईएफटीए देशों से होने वाले आयात पर लगभग 80-85 प्रतिशत आयात शुल्क खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, जबकि इएफटीए 99.6 प्रतिशत भारतीय निर्यात के लिए शुल्क-मुक्त पहुंच प्रदान करता है। शुल्क कटौती से कुछ संवेदनशील कृषि उत्पादों को बाहर रखा गया है। इएफटीए के बाजार पहुंच प्रस्ताव में 100 प्रतिशत गैर-कृषि उत्पाद और प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद पर शुल्क रियायत

शामिल है। सोने पर शुल्क अछूता रहा है। भारत में निवेश प्रोत्साहन इस समझौते का दूसरा मुख्य अंश है।

इएफटीए ने 15 वर्षों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआइ) में 100 अरब डॉलर की बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो भारत समझौते से बाहर निकलने के लिए स्वतंत्र होगा। यूरोपीय देशों के साथ हुआ यह समझौता सीमा शुल्क प्रक्रियाओं, व्यापार नियमों और तकनीकी बाधाओं को सरल बनाने, संभावित रूप से सीमाओं के पार माल के प्रवाह में तेजी लाने और व्यवसायों के लिए परिचालन लागत को कम करने का प्रयास करता है। यह समझौता आइपी सुरक्षा मानकों को मजबूत करता है, जिससे भारतीय कंपनियों को नवीन उत्पादों और बौद्धिक संपदा से लाभ हो सकता है। जेनेरिक दवाओं में भारत के हितों और पेटेंट से संबंधित चिंताओं को इसमें पूरी तरह से संबोधित किया गया है। टीइपीए के समर्थकों का मानना है कि यह समझौता भारत के लिए आर्थिक विकास के एक नये युग की शुरुआत करेगा। इस समझौते से विशेष रूप से भारतीय कपड़ा, दवाओं और कृषि उत्पादों (संवेदनशील वस्तुओं को छोड़कर) के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि की उम्मीद है। लक्षित निवेश बुनियादी ढांचे के विकास, उद्योगों के आधुनिकीकरण और रोजगार सृजन के लिए पूंजी का एक बहुत जरूरी इंजेक्शन प्रदान कर सकता है। तकनीकी रूप से उन्नत इएफटीए देशों के भारत में निवेश से ज्ञान और तकनीक का हस्तांतरण होने की प्रबल संभावना है। बढ़े हुए व्यापार और निवेश से विभिन्न क्षेत्रों में 10 लाख रोजगार के नये अवसर पैदा होने की संभावना है। सरल व्यापार प्रक्रिया से भारतीय व्यवसाय विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बन सकते हैं।

यह समझौता व्यापार बढ़ाने का वादा करता है, लेकिन भारतीय उद्योगों, खासकर कृषि क्षेत्र, के लिए चिंताएं भी पैदा करता है। बड़ी भारतीय कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने की उनकी बेहतर क्षमता के कारण इस समझौते से अधिक लाभ हो सकता है। समझौते के लाभ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में असमान रूप से वितरित किये जा सकते हैं। बेहतर व्यापार अवसंरचना वाले तटीय क्षेत्रों को भौगोलिक रूप से वंचित क्षेत्रों की तुलना में अधिक लाभ हो सकता है।

यह लोकसभा चुनाव भारत के सुनहरे भविष्य का चुनाव है : देव

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पत्रकार वार्ता में कहा : प्रधानमंत्री के रूप में मोदी का चुनाव यानी भारत को विकसित देश बनाना

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा है कि जनता ने भाजपा को सुशासन, संवेदनशीलता, सेवा और संस्कार का प्रतिसाद देने का मन बना लिया है और सभी 11 सीटों पर रिकॉर्ड बहुमत से भाजपा को जीत मिलने जा रही है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बचे हुए दोनों टापू भी इस बार भाजपा की सुनामी में डूबने वाले हैं। भाजपा कार्यकर्ता इस बार कोरबा और बस्तर में भी जीत का परचम फहराने वाले हैं। श्री देव ने कहा कि प्रदेश का एक-एक भाजपा कार्यकर्ता कार्यकर्ता अबकी बार 400 पार के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्राण-पण से जुटा हुआ है। छत्तीसगढ़ की जनता और हमारे 40 लाख निष्ठावान कार्यकर्ता 11 सीटों के रूप में इस चुनाव में मोदी जी को अपना शत प्रतिशत समर्थन और सहयोग देने वाले हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष देव ने केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए तारीखों की घोषणा किए जाने के बाद एकात्म परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में शनिवार को आहूत पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा की चुनावी तैयारी विधानसभा चुनाव पूर्ण होने के दूसरे दिन से ही आरंभ हो गई थी। भाजपा सभी चुनावों को गंभीरता से लेती है। हमें पूर्ण विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की समझदार जनता भाजपा को पूरी 11 सीटें देकर एक व्यापक, चमत्कारिक जनादेश देने जा रही है। मोदी की गारंटी और विष्णु के सुशासन को

छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर खिलेगा कमलः मुख्यमंत्री

लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ट्वीट कर कहा, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुकी है. समूचा भारत लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने के लिए उत्साहित हैं. बीते दस वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल और मजबूत नेतृत्व में सबका साथ-सबका विकास के ध्येय को फलीभूत करते हुए देश ने अभूतपूर्व प्रगति की. सीएम साय ने कहा, सरकार में आते ही हमने केवल 3 महीनों में ही छत्तीसगढ़ में मोदी की प्रमुख गारंटियों को प्राथमिकता से पूरा किया. हम प्रदेश की सभी 11 लोकसभा सीटों में कमल खिलाने के प्रति पूरी तरह आश्वस्त हैं. हम केंद्र में फिर से मोदी को लाएंगे और भारत को विश्वगुरु बनाएंगे.

राज्य की जनता ने हाथो-हाथ लिया है और पूरे राज्य में अभूतपूर्व संतोष और खुशी का माहौल है। यह समर्थन नए भारत और विकसित भारत के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री सपनों में नहीं, संकल्प में यकीन करते हैं। श्री देव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं के परिश्रम के परिणामस्वरूप भाजपा को 46 प्रतिशत मत को साथ 54 सीटों पर जीत मिली। 2018 के विधानसभा चुनाव 2018 में भाजपा 15 सीटों पर जीती, लेकिन चार माह बाद लोकसभा चुनाव में भाजपा को 9 सीटों पर जीत मिली थी। 2023 में 54 सीटों पर भाजपा को जीत मिली है, इसलिए अबकी बार 11 सीटों को जीतने का लक्ष्य है। पिछले चुनाव के परिणाम से उत्साहित कार्यकर्ता फिर से लोकसभा चुनाव की तैयारी में दिन-रात जुटे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि उन्हें यह बताते हुए गर्व और संतोष का अनुभव हो रहा है कि भाजपा कार्यकर्ता और नेतागण बूथ से लेकर प्रदेशस्तर तक की सभी चुनावी तैयारियों में दिन-रात एक कर रहे हैं। सभी अनुभवी नेताओं और देव-दुर्लभ कार्यकर्ताओं से अपील है कि अबकी बार 400 पार के लक्ष्य को प्राप्त करने तक एक क्षण के लिए भी रुकें नहीं, थकें नहीं। श्री देव ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं का संकल्प है कि जिस तरह से देश ने हाल ही में दो बार दीवाली मनाई, उसी तरह से हम दो बार होली भी मनाएंगे। लोकसभा चुनाव में 400 पार करने की संकल्प की सिध्दि के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामाख्या तक भाजपा का परचम लहराना होगा और पूरे प्रदेश की जनता और कार्यकर्ता एकमत होकर, एकजुट होकर इस काम में जुटे हुए हैं।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में भाजपा की सरकार ने मात्र 90 दिन की अल्पावधि में जनता के हित के लिए जो काम किया, जो योजनाएँ बनाई और उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया, वह 10 वर्ष के मोदी सरकार के कार्यकाल का एक छोटा-सा मॉडल है। केवल 90 दिनों में ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने 14 दिसंबर को पहली कैबिनेट में 18 लाख प्रमं आवास को स्वीकृति दी गई। 25 दिसंबर को बकाया बोनस का भुगतान किया गया। धान खरीदी की लिमिट प्रति एकड़ 21 क्विंटल की गई।

मुख्यमंत्री साय प्रदेश के सभी विस क्षेत्रों में सभाएं लेंगे-शर्मा

भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक व पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का छत्तीसगढ़ प्रवास होगा। इसी क्रम में मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सभाएं लेकर प्रचार करेंगे। पार्टी की चुनावी तैयारियों की विस्तार से चर्चा करते हुए श्री शर्मा ने बताया कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव की दृष्टिकोण से छत्तीसगढ़ को तीन कलस्टरों में विभाजित कर प्रभारी व सह प्रभारियों की नियुक्ति की। इसी प्रकार संभाग प्रभारी एवं सह प्रभारियों की नियुक्तियां की गई है। श्री शर्मा ने कहा कि आचार संहिता लगने से पहले ही पूरे 11 प्रत्याशियों की घोषणा होने का बाद लोकसभा क्षेत्रों एवं विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है। सभी लोकसभा प्रत्याशियों का अपने-अपने लोकसभा क्षेत्रों में सघन दौरा प्रारंभ हो चुका है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन की दृष्टि से 37 कमेटियों का गठन किया गया है। चुनाव सुचारू रूप से संचालित करने के लिए चुनाव प्रबंधन संयोजक व सह प्रबंधकों की नियुक्ति हो चुकी है। प्रधानमंत्री श्री मोदी के 10 वर्ष के एवं भाजपा की प्रदेश सरकार के 3 माह के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में तीन-तीन प्रचार रथ चलेंगे। भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक श्री शर्मा ने कहा कि विधानसभा चुनाव सम्पन्न होने बाद से ही भाजपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विभिन्न कार्यक्रमों की रचना की। इस क्रम में गाँव चलो अभियान का प्रारंभ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया। इस अभियान के तहत प्रदेश के 20 हजार गांवों में भाजपा कार्यकर्ता गए। इस अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जशपुर में, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण देव रायपुर ग्रामीण में एवं गांव चलो अभियान के प्रदेश संयोजक नारायण चंदेल जांजगीर में प्रवास कर 24 घंटे का समय व्यतीत किए। सांगठनिक 35 जिलों के 280 स्थानों पर शक्ति वंदन कार्यक्रम किया गया। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. सरोज पांडेय के नेतृत्व मेंशक्ति वंदन अभियान के तहत 8 एवं 9 फरवरी 2024 को जिला स्तरीय एन.जी.ओ. एवं महिला स्व. सहायता समूह का संवाद कार्यक्रम किया गया। शक्ति वंदन कार्यक्रम 08 फरवरी से पूरे प्रदेश में आयोजित किया गया। श्री शर्मा ने बताया कि वादे के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अब तक प्रदेश के 10 हजार से अधिक लोगों को भगवान श्रीराम लला के दर्शन के लिए अयोध्या श्रध्दा ट्रेन के माध्यम से भेजा गया है। छत्तीसगढ़ के सभी लोगों के लिए भाजपा की प्रदेश सरकार श्रीराम लला के दर्शन हेतु विशेष ट्रेन चला रही है।

आदर्श आचार संहिता लागू होते ही संपत्ति विरूपण की कार्रवाई प्रारंभ

रायपुर। ज़िला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर डाक्टर गौरव सिंह के निर्देश पर शनिवार को आचार संहिता लगते ही संपत्ति विरूपण की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। इसके तहत 24 घण्टे के भीतर शासकीय संपति से और 48 घण्टों के भीतर सार्वजनिक स्थानों से प्रचार-प्रसार की सामग्री हटाई जानी है। नगरीय निकायों में और जनपद पंचायतों में टीम बनाकर यह कार्रवाई आज रायपुर ज़िले के चारो ब्लॉक धरसीवां ब्लॉक,आरंग ब्लॉक,तिल्दा ब्लॉक एवं मंदिर हसौद ब्लॉक में प्रारंभ कर दी गई है। साथ ही नगरीय निकायों में भी यह कार्यवाही की जा रही है। शासकीय प्रचार प्रसार वाले होर्डिंग को कवर किया गया है ,वही वॉल पेंटिंग की पोताई की गई है।

लोकसभा निर्वाचन के लिए स्थानीय निर्वाचन शाखा कलेक्टर परिसर में शिकायत सेल कंट्रोल रूम का गठन किया गया है। जहां पर नोडल अधिकारी व सहायक नोडल अधिकारी के मार्गदर्शन में ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। इसके नोडल अधिकारी अपर कलेक्टर बीसी साहू है। कंट्रोल रूम का संपर्क नंबर 0771-2445785 जारी किया गया है।

लोकसभा निर्वाचन-2024 के दौरान कोलाहल विहीन वातावरण बनाए रखने के उद्देश्य से बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग को निषेध कर दिया है। निर्वाचन प्रचार-प्रसार एवं आमसभा प्रचार जुलूस वाहन इत्यादि के लिए क्षेत्र के संबंधित सक्षम प्राधिकारी से लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रात: 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक की अवधि में किया जा सकता है।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. गौरव कुमार सिंह ने जनप्रतिनिधियों को आबंटित वाहन वापस लेने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में आदेश जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है।

अत: निर्वाचन की घोषणा की दिनांक से निर्वाचन कि परिणाम घोषित होने के दिनांक तक केन्द्र राज्य शासन के उपक्रम, संयुक्त क्षेत्र के उपक्रमों स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिला पंचायतों, जनपद पंचायतो, ग्राम पंचायतों, नगर पंचायतों, विपणन बोर्ड, विपणन संस्थाओं, कृषि उपज मंडी समिति प्राधिकरणों या अन्य ऐसे निकाय जिनमें सरकारी धन का कितना भी छोटा अंश निवेश किया गया हो, के वाहनों के उपयोग के किसी भी प्रकरण की अनुमति संसद सदस्य, लोकसभा सदस्य या राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों अथवा अभ्यर्थियों या निर्वाचन से संबंधित किसी व्यक्ति को नहीं दिए जाने के आदेश है।

लोस चुनाव : पुलिस और जिला प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च

रायपुर. लोकसभा चुनाव को लेकर रायपुर पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन ने राजधानी के पुलिस ग्राउंड में फ्लैग मार्च निकाला. फ्लैग मार्च में रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह और एसपी संतोष सिंह भी शामिल हुए. दो दलों में पुलिस और ज़िला प्रशासन की टीम को रवाना किया गया. कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने बताया, आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. आज फ्लैग मार्च निकालकर पूरी व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया गया. रायपुर एसपी संतोष सिंह ने बताया, जिले में आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकाला है. फ्लैग मार्च का उद्देश्य लोगों में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन की तैयारी दिखाना है.

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

जिले में धारा 144 लागू

रायपुर। लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं भयमुक्त वातावरण में मतदाताओं द्वारा मताधिकार का प्रयोग करने के दृष्टिगत जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा अस्त्र-शस्त्र धारण करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा किए जाने के साथ ही निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। चुनाव प्रक्रिया में असामाजिक तत्वों द्वारा भय एवं आतंक का वातावरण निर्मित कर शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष चुनाव में बाधा खड़ी न की जा सके तथा मतदाताओं में किसी भी प्रकार का भय पैदा न हो एवं मतदाता भयमुक्त वातावरण में निर्भय होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके, इसके मद्देनजर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने एक आदेश जारी कर 16 मार्च 2024 से जिले में धारा 144 लागू कर दी है तथा आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का शस्त्र, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छुरी, कुल्हाड़ी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकरा, सांग एव बल्लम अथवा अन्य अस्त्र शस्त्र लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं निकलेगा। जो व्यक्ति शासकीय कर्तव्य पर है वे ड्यूटी के दौरान अस्त्र-शस्त्र धारण कर सकेंगे। रायपुर जिले के अंदर कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के न तो कोई सभा करेगा ना ही कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा तथा ना ही कोई धरना देगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह या व्यक्ति के विरूद्ध धारा दण्ड संहिता के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

रविवार को कुछ क्षेत्रों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार

रायपुर। प्रदेश में मौसम का मिजाज रविवार से बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रविवार को अंधड़ के साथ बारिश होने व ओलावृष्टि की संभावना है। इसके साथ ही अगले तीन दिनों में अधिकतम तापमान में दो से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना है। शनिवार को प्रदेश भर में तिल्दा सर्वाधिक गर्म रहा और एआरजी तिल्दा का अधिकतम तापमान 37.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं रायपुर का अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से एक डिग्री ज्यादा और न्यूनतम तापमान सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा रहा। शनिवार को रायपुर सहित प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहा और कुछ क्षेत्रों में आंशिक रूप से बादल छाए रहे। मौसम विज्ञानी एचपी चंद्रा ने बताया कि द्रोणिका के प्रभाव से मौसम का मिजाज बदल रहा है। रविवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में अंधड़ के साथ बारिश के आसार है। अधिकतम तापमान में गिरावट की संभावना बनी हुई है तथा वर्षा का क्षेत्र मध्य छत्तीसगढ़ रहेगा। 17 से लेकर 19 मार्च तक प्रदेश का मौसम का ऐसा ही रहेगा। रविवार 17 मार्च को जशपुर,सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर, कोरबा, बिलासपुर, बलौदाबाजार, महासमुंद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, कोंडागांव, कांकेर, बालोद, दुर्ग, बेमेतरा,रायपुर में तेज अंधड़ के साथ बादल भी गरजेंगे।

ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज एथलेटिक्स प्रतियोगिता 17 से

रायपुर। स्वामी विवेकानंद स्टेडियम कोटा में मार्च को सिविल सेवा राज्यस्तरीय एथलेटिक्स खेल चयन ट्रायल प्रतियोगिता हुई। जिसमें प्रदेश से 150 खिलाड़ी आए हुए थे। रायपुर जिले से भी कर्मचारी शामिल हुए जिसमें 08 खिलाडियों का चयन राष्ट्रीय सिविल सर्विसेज खेल के लिए हुआ । प्रतियोगिता चंडीगढ़ में 19 मार्च से होना है। चयनित खिलाड़ियों में लक्ष्मीनारायण वर्मा प्रधानपाठक प्राथमिक शाला सिलयारी (धरसींवा) लम्बीकुद में योगेन्द्र त्रिपाठी व्यायाम शिक्षक भरत देशा उत्कृष्ट विद्यालय खरोरा 100 मी. दौड़ ट्रिपल जम्प में झरना साहू शास. उच्चतर माध्यमिक शाला देवरी ज्वेलीन थ्रो में हुआ। जो.एल पिन्हेरो पी सी. एफ. कार्यालय नवारायपुर 100 मी, 4×100 में एस कुमार मण्डावी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग रायपुर परिक्षेत्र 800 मी., 4×100 मीटर रिलेरेस में हुआ। आनंद कुमार राठिया छग विधान सभा सचिवालय रायपुर का चयन 200 मी., 800 मी. में हुआ । थिरमनदास छग विधानसभा सचिवालय रायपुर 1500 मीटर और डी. एस.एन राव कार्यपालन अभियन्ता राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक 01लोक निर्माण विभाग रायपुर का चयन तवाफेंक एवं गोला फेंक में हुआ।

मृतक साधराम के परिजनों से मिले प्रवीण तोगड़िया

रायपुर। मृतक साधराम यादव के परिजनों से मिलने अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया कवर्धा पहुंचे. उन्होंने परिजनों से मुलाकात के बड़ा बयान दिया है. तोगड़िया ने कहा, भारत में हमारे बेटे सर काटने वाले जेहादियों से अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है. हमने भव्य राम मंदिर तो बनाया, लेकिन साधराम को बचा नहीं पाए. उन्होंने कहा, राम मंदिर बनाने की सार्थकता तभी है जब एक भी हमारा बेटा-बेटी जेहादियों का भोग ना बने. प्रवीण तोगड़िया ने आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से तीन महीने में फांसी देने की मांग की और आरोपियों के घरों में बुलडोजर चलाने की बात कही.

एंबुलेंस से मरीजों को अस्पताल ले जाने में अब ट्रैफिक नहीं बनेगा बाधा

रायपुर। एंबुलेंस से मरीजों को अस?पताल ले जाने के लिए अब ट्रैफिक सिग्नल बाधा नहीं बनेगा। चौक-चौराहों पर एंबुलेंस के पहुंचते ही सिग्नल ग्रीन हो जाएगा। एंबुलेंस के संचालन के लिए रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड, नगर निगम रायपुर और यातायात पुलिस ने ग्रीन कारिडोर योजना तैयार की है। जिसके तहत ट्रैफिक सिग्नल पर एंबुलेंस दिखाई देते ही ग्रीन कारिडोर बन जाएगा। जिससे एंबुलेंस का रास्ता साफ होगा और मरीज को समय से अस्पताल पहुंचने में मददगार होगा। यह व्यवस्था को रायपुर में शुरू कर दी गई है। रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के प्रबंध संचालक अबिनाश मिश्रा के अनुसार मरीजों को अस्पताल तक पहुंचाने त्वरित सेवा प्रदान करने एक ऐसी स्वचलित प्रणाली तैयार की गई है, जिसमें जीपीएस इनेबल्ड 108-एंबुलेंस से संदेश प्राप्त होते ही कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के सिग्नल ग्रीन हो जाएंगे। इससे एंबुलेंस न्यूनतम समय में गंतव्य अस्पताल तक पहुंच पाएंगे। उन्होंने बताया की पायलट प्रोजेक्ट के तहत शहर में सेवा दे रहे 108 से जुड़े एंबुलेंस को इससे जोड़ा गया है और आगे चलकर दूसरे जिलों व निजी व शासकीय अस्पतालों से संबद्ध एंबुलेंस को भी इससे जोड़ा जाएगा।

क्रेडा द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय शनिवार को छत्तीसगढ़ अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) द्वारा आयोजित सड़क सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए तथा इलेक्ट्रिक वाहन रैली को झंडी दिखाकर रोड शो का शुभारंभ किया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रोड शो मुख्यमंत्री निवास से शुरू होकर भगत सिंह चौक, तेलीबांधा चौक ,वीआईपी चौक और फुंडहर होते हुए एनर्जी पार्क तक किया गया।

इस अवसर पर उन्होने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में परिवहन के क्षेत्र में कई नई विकासशील योजनाओं द्वारा देश हित में कार्य किया जा रहा है। 2021 में स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में आयोजित सम्मेलन में भारत के महत्वाकांक्षी पांच सूत्रीय- पंचामृत लक्ष्य के विषय पर पूरे विश्व को अवगत कराया उन्होने कराया था। इस दिशा में क्रेडा द्वारा विभिन्न अक्षय ऊर्जा आधारित परियोजनाओं के माध्यम से जनहित में कार्य किया जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंचामृत लक्ष्य अंतर्गत स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में वर्ष 2030 तक देश अपने निर्भरता पारंपरिक ऊर्जा के स्त्रोतों पर कम करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को हासिल करने हेतु परिवहन क्षेत्र में इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग एक मील का पत्थर साबित होगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाने हेतु देश में एक नई लहर प्रारंभ हुई है जिसके तहत छत्तीसगढ़ में 39 हजार 802 दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन ,17 हजार 956 तीन पहिया वाहन एवं 1596 चार पहिया वाहन संचालित हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों से ना कोई जहरीला धुआं निकलता है और न ही पेट्रोल डीजल की आवश्यकता होती है । पेट्रोल डीजल वाहन के मुकाबले इलेक्ट्रिक वाहन एक सस्ता एवम टिकाऊ विकल्प है । क्रेडा द्वारा राज्य में सौर संयंत्रों के माध्यम से समाज के हर वर्ग एवं हर तबके के लोगों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मां महामाया एयरपोर्ट अम्बिकापुर को उड़ान हेतु सिविल एविएशन से लाइसेंस जारी

रायपुर। सरगुजा (अम्बिकापुर) जिले के दरिमा हवाई अड्डा से विमान संचालन की क्षेत्रवासियों की बहुप्रतिक्षित मांग आज पूरी हो गई है।

भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन कार्यालय द्वारा मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा अम्बिकापुर को उड़ान हेतु लाइसेंस जारी कर दिया है। सरगुजा जिले में लगातार डीजीसीए की टीम द्वारा एयरपोर्ट अधोसंरचना और आवश्यक मानदंडों का निरीक्षण किया जा रहा था। इसी कड़ी में गत दिवस बीसीएएस यानी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की टीम द्वारा अंतिम निरीक्षण किया गया था। यात्रियों और उड़ान संचालन की सुरक्षा के लिए विकसित बुनियादी ढांचे की स्थिति और सुविधाओं के लिए बीसीएएस द्वारा निरीक्षण किया गया था। जिसमें सुरक्षित उड़ान संचालन के लिए हवाई अड्डे की उपयुक्तता की पुष्टि की गई जहां टीम ने सभी पहलुओं पर संतोष जताया।

अनंतिम मंजूरी जारी करने के लिए रिपोर्ट बीसीएएस मुख्यालय दिल्ली को भेजी गई जिसके परिणाम स्वरूप अगले ही दिन 15 मार्च को विमान संचालन का आदेश जारी कर दिया गया। अम्बिकापुर एयरपोर्ट के लाईसेंसिंग के साथ राज्य में अब आरसीएस योजनांतर्गत बिलासपुर, जगदलपुर सहित 03 लाईसेंस युक्त एयरपोर्ट हो गये हैं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.